नई दिल्ली ■ बुधवार 29 अप्रैल 2026 ■ मूल्य 5.00 ■ वर्ष 14 ■ अंक 31 ■ पृष्ठ 08

JBT जनभावना टाइम्स
www.thejbt.com
निष्पक्ष और निर्भीक खबर
दिल्ली, गौतमबुद्ध नगर, देहरादून, लखनऊ, अलीगढ़, मथुरा, हिसार, कैथल, करनाल एवं मुजफ्फरनगर से प्रकाशित

04 अब कमजोर मानसून व अल नीनो का जोखिम | 07 मैराथन रिकॉर्ड धारक ने स्वयं कराए कई डोप टेस्ट | जब आपके साथ माता-पिता हों तो उनसे प्यार करें अंकिता लोखंडे 08

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में 142 सीटों के लिए मतदान आज

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के तहत बुधवार को होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 142 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील और अतिसंवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

इस चरण में 3.21 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दूसरे चरण में कुल 3,21,73,837 मतदाता हैं। इनमें 1,64,35,627 पुरुष, 1,57,37,418 महिला और 792 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 4,12,668 नए मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। चुनाव आयोग ने 1,96,801 ऐसे मतदाताओं की पहचान की है, जिनकी उम्र 85 वर्ष से अधिक है। वहीं 3,243 मतदाता 100 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं। इसके अलावा 57,783 दिव्यांग मतदाता भी लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेंगे। इस चरण में कुल 1,448 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 1,228 पुरुष और 220 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। दक्षिण 24 परगना जिले का भांगड़ विधानसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा चर्चा में है, जहां 19 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं हुगली जिले के गोघाट में सबसे कम केवल 5 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा।

उत्तर 24 परगना की 33 सीटों पर इस बार बड़ा चुनावी मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां 71 लाख से अधिक मतदाता बंगाल की राजनीतिक दिशा तय करेंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से कोलकाता का जोरासांको सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल केवल 3.48 वर्ग किलोमीटर है। वहीं, नदिया जिले का कल्याणी विधानसभा क्षेत्र 135 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है।

मतदाताओं की संख्या के हिसाब से भाटपाड़ा में सबसे कम 1,17,195 मतदाता हैं, जबकि हुगली के चुंचुड़ा में सबसे अधिक 2,75,715 मतदाता हैं। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इस बार तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। महिलाओं के सम्मान में 8,845 मतदान केंद्र पूरी तरह महिला कर्मियों द्वारा संचालित किए जाएंगे। सभी 41,001 मतदान

केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी, ताकि हर गतिविधि पर निगरानी रखी जा सके। चुनाव में 55,331 बैलेट यूनिट, 55,162 कंट्रोल यूनिट और 59,463 वीवीपैट मशीनों का उपयोग किया जाएगा।

साथ ही ईवीएम और बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें, नाम, क्रमांक और चुनाव चिन्ह बड़े अक्षरों में दिए गए हैं, ताकि मतदाताओं को सुविधा हो। दूसरे चरण के मतदान में कई संवेदनशील क्षेत्र हैं इसलिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती है। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 2,407 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस भी पूरी तरह सक्रिय रहेगी। सबसे अधिक 507 कंपनियां उत्तर 24 परगना जिले में तैनात होंगी। बांग्लादेश सीमा और सुंदरबन क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिलों में तटीय गश्त भी बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों और अंदरूनी गलियों में सुरक्षा बल लगातार गश्त करेंगे। इसके लिए 160 मोटरसाइकिलों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान तैनात किए जाएंगे, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मौके पर पहुंचेंगे।

मतदान से पहले माहौल बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए तृणमूल कांग्रेस के एक पार्षद सहित कुल 1,543 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, पूर्व बर्धमान जिले की बर्धमान नगरपालिका के वार्ड संख्या 22 से टीएमसी पार्षद नारू गोपाल भाकट को भाजपा नेता के घर पर हमले और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने सोमवार को बताया कि मतदान के दौरान न तो फर्जी वोटिंग होगी और न ही किसी प्रकार की गड़बड़ी होने दी जाएगी। अंतिम चरण के लिए तैयारियों को और अधिक मजबूत किया गया है। उल्लेखनीय है कि 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान में पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड 93.19 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था, जिसने चुनावी उत्साह को और स्पष्ट कर दिया। बुधवार को जिन 142 सीटों पर मतदान होना है, उनमें 23 सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। इस सूची में जादवपुर सबसे ऊपर है।

पश्चिम बंगाल के साथ-साथ केरल, असम, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना भी 4 मई को होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल का यह सियासी 'खेला' बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। पहले चरण के भारी मतदान ने चुनावी समीकरणों को बदल दिया है और मुकाबले को बेहद कांटे का बना दिया है। अब सभी की नजरें 29 अप्रैल की वोटिंग, एग्जिट पोल और अंततः 4 मई को आने वाले अंतिम परिणाम पर टिकी हैं, जब यह तय होगा कि बंगाल की सत्ता किसके हाथों में जाएगी।

महिला आरक्षण लागू करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा : नरेन्द्र मोदी

वाराणसी के लिए 6330 करोड़ की 163 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश को विकसित बनाने का क्रम अनवरत चल रहा है। उसका सबसे मजबूत स्तंभ भारत की नारी है। आज सभी माताओं, बहनों से एक महायज्ञ की शुरुआत के लिए आशीर्वाद लेने आया हूं। यह लक्ष्य लोकसभा और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना है। हमने प्रयास किया लेकिन सपा और कांग्रेस जैसे दलों ने यह नहीं होने दिया। हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। आरक्षण लागू हो, इसमें मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी वाराणसी में छह हजार 330 करोड़ की लागत वाली 163 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के बाद नारी वंदन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी दो अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा रवाना किया। यह ट्रेनें बनारस से पुणे एवं अयोध्या से मुंबई के लिए चलेंगी। उन्होंने बनास डेयरी के तीन लाख 21 हजार 813 दुग्ध उत्पादकों को बोनस राशि का भी उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ग्राउंड पर नारी वंदन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी काशी माता श्रृंगार गौरी, अन्नपूर्णा, विशालाक्षी, माता संकटा और मां गंगा की दिव्य धरती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भोजपुरी में माताओं, बहनों को प्रणाम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को विकसित बनाने का क्रम अनवरत चल रहा है। उसका सबसे मजबूत स्तंभ भारत की नारी है। आज सभी माताओं, बहनों से एक महायज्ञ की शुरुआत के लिए आशीर्वाद लेने आया हूं। यह लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना है। प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस, सपा और टीएमसी समेत अन्य विपक्षी दलों को महिला विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण लागू करने का हमने प्रयास किया लेकिन सपा और कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों ने यह नहीं होने दिया। हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। आरक्षण लागू हो, इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि महिला के मजबूत होने से पूरा परिवार और समाज मजबूत होता है। अतीत में महिलाओं को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है। बेटियों को तमाम सवालों का सामना करना पड़ा है। देश की ज्यादातर बेटियां इससे गुजरीं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 25 साल पहले जब गुजरात में मुख्यमंत्री बना तो बेटियों के लिए दो योजनाएं शुरू कीं। वर्ष 2014 में केंद्र में हमारी सरकार आई तो बेटियों की समृद्धि और सुविधा से जुड़ी कई योजनाएं शुरू की गयीं। दो साल पहले काशी से ही सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गयी। यह योजना बेटियों के आगे बढ़ने में बड़ी भूमिका अदा कर रही है। पढ़ाई, कमाई और दवाई के साथ करोड़ों बहनों के नाम पर पहली बार कोई प्रापर्टी रजिस्टर हुई है। उन्होंने भोजपुरी में कहा कि आज हमार माई बहन अपने घर कर मालकिन बनत है।

उन्होंने कहा कि आपने यहां यूपी में हालात बदलते हुए देखा है। सपा की सरकार में बेटियों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया था। आज बेटियों की ओर देखने वालों का क्या हश्र होता, यह सब जानते हैं। महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं। ऐसे कदम बेटियों को सुरक्षा देते हैं। बहनों की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया गया। स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर तीन करोड़ बहने लखपति दीदी बन चुकी हैं। लखपति दीदी बनने में डेयरी की भी बड़ी भूमिका है। आज डेयरी से जुड़ी बहनों को 106 करोड़ रुपये बोनस के रूप में मिले हैं। काशी की बहनों से कहना चाहता हूं कि अभी तो यह शुरुआत है। भाजपा सरकार बहनों को आत्मनिर्भर बना रही है। मोदी ने कहा कि बेटियों के लिए सभी तीनों सेनाओं में स्थान मिला है। आज हर क्षेत्र में हर मोर्चे पर बेटियों मजबूत कार्य कर रही है। देश की नई संसद बनाने के पीछे बहनों की भागीदारी बढ़ाना एक महत्वपूर्ण कारण था। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए संसद में नया कानून लाया गया लेकिन सपा, कांग्रेस और टीएमसी जैसे दलों ने उसे रोक दिया। 40 साल से ये दल इस पर ब्रेक लगाए हुए हैं। वे बहनों को विधानसभा और संसद नहीं आने देना चाहते हैं। वे जानते हैं कि अगर मजबूत नेतृत्व प्रदान करने वाले बहनें संसद आ जाएंगी तो इनकी पोल खुल जाएगी। पश्चिम बंगाल, असम से लेकर केरलम तक बहनों से इनके (विपक्ष) खिलाफ मजबूत वोट किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में हुए विकास कार्यों को भी गिनाते हुए कहा कि इन कार्यों से यहां के लोगों को सबसे अधिक लाभ हो रहा है। हमारी काशी अविनाशी है। यह निरंतर चलने वाला शहर है। इसी तरह विकास का पहिया भी लगातार गतिमान है। इस मौके पर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उप्र भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक व अन्य नेता मौजूद रहे।

गुजरात: सभी 15 नगर निगमों में भाजपा की जीत

आप 27 से घटकर 4 पर सिमटी

अहमदाबाद। गुजरात की सभी 15 महानगरपालिकाओं के चुनाव में इस बार भी भाजपा का दबदबा कायम रहा। सूरत महानगरपालिका में भाजपा ने एक बार फिर प्रचंड जीत दर्ज करते हुए 120 में से 115 सीटों पर कब्जा कर लिया है। पिछले 30 वर्षों से जारी भाजपा का एकछत्र शासन अगले पांच वर्षों तक भी बरकरार रहेगा।

वर्ष 2021 में 27 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी इस बार मात्र 4 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस, जो पिछली बार खाता भी नहीं खोल सकी थी, इस बार केवल 01 सीट जीतने में सफल रही है। इन चुनावों का आयोजन एसआईआर(स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) प्रक्रिया और 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद हुआ। हालांकि, इन बदलावों के बावजूद मतदान प्रतिशत में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई। राज्यभर में 49 लाख से अधिक मतदाता मतदान के लिए बाहर ही नहीं निकले। मतदान प्रतिशत की बात करें तो वापी महानगरपालिका में पहली बार हुए चुनाव में सबसे अधिक 72.29 फीसद मतदान दर्ज किया गया, जबकि गांधीधाम में सबसे कम 46.03 फीसद मतदान हुआ। राज्य की सभी 15 महानगरपालिकाओं में भाजपा ने अपना परचम लहराया है।

विपक्ष को केवल नाममात्र की सीटों से संतोष करना पड़ा। चुनाव से पहले कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे, लेकिन इसका असर मतदान या परिणामों पर नजर नहीं आया। 15 महानगरपालिकाओं में से अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर और जामनगर पुरानी महानगरपालिकाएं हैं, जबकि महेसाणा, सुरेंद्रनगर, आनंद, मोरबी, नडियाद, वापी, नवसारी, पोरबंदर और गांधीधाम नई महानगरपालिकाएं हैं, जहां पहली बार चुनाव हुए हैं। अहमदाबाद महानगरपालिका के खाड़िया वार्ड में, जो भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है, कांग्रेस ने जीत दर्ज कर भाजपा को झटका दिया है। यहां भाजपा के चारों उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है।

संक्षिप्त खबरें

लखीमपुर खीरी : सड़क हादसे में चार युवकों की मौत व दो घायल

लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में फरधान थाना क्षेत्र स्थित बेहजम रोड पर सोमवार देर रात तेज रफ्तार एक कार ने दो बाइकों में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों बाइकों पर सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर जांच शुरू कर दी। क्षेत्राधिकारी नगर विवेक तिवारी ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों की पहचान हो गई हैं, जिनमें नीमगांव थाना क्षेत्र निवासी हितेश शुक्ला (42), सोनौरा गांव के हरि किशन (40), बासारा गांव के अनुज कुमार (35) और आदर्श शामिल हैं। वहीं, दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गये। घटना की जानकारी मिलते ही सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों तत्काल अस्पताल भिजवाया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है।

मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस की कैपेसिटी 16 से बढ़ाकर 20 कोच हुई

मुंबई। भारतीय रेलवे ने मंगलवार को मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस की कैपेसिटी 16 से बढ़ाकर 20 कोच कर दी है। इसका मकसद देश के सबसे बिज़ी कॉरिडोर में से एक पर पैसेंजर की सुविधा बढ़ाना और बढ़ती डिमांड को पूरा करना है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि यह कदम ज़्यादा डिमांड वाले रूट पर कैपेसिटी बढ़ाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है, क्योंकि वंदे भारत सर्विस को लगातार अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। भारतीय रेलवे की ओर से अब तक 162 वंदे भारत सर्विस शुरू हो चुकी हैं, जिससे कई कॉरिडोर पर यात्रा का समय 45 प्रतिशत तक कम हो गया है। इनमें से 90 सर्विस 8-कोच के साथ, 38 सर्विस 20-कोच के साथ और 34 सर्विस 16 कोच के साथ चल रही हैं। इससे पता चलता है कि लगभग 23.45 प्रतिशत वंदे भारत सर्विस को 20 कोच में अपग्रेड किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने थानों में CCTV के लिए इस्तेमाल फंड का केंद्र और राज्यों से मांगा हिसाब

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने देशभर के थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए फंड के इस्तेमाल को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों से हिसाब मांगा है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने एमिकस क्यूरी सिद्धार्थ दवे को 6 मई को केंद्र और राज्यों के गृह सचिवों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि वो ये जानना चाहता है कि राज्यों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए जो भारी फंड दिया गया था उसका उपयोग सही जगह पर हुआ कि नहीं। मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 6 मई को होने वाली बैठक में केंद्र सरकार के गृह सचिव या उनकी ओर से नामित अधिकारी मौजूद रहें। ये नामित अधिकारी संयुक्त सचिव या अतिरिक्त सचिव रैंक से नीचे का नहीं होने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के गृह सचिवों को भी अनिवार्य रुप से हिस्सा लेना होगा। कोर्ट ने कहा कि इस बैठक में राज्यों से सिर्फ इस फंड के इस्तेमाल पर जवाब मांगा जाएगा और इसकी पूरी रिपोर्ट 13 मई को कोर्ट में पेश की जाए। सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने कोर्ट को फंड के बंटवारे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रशासित प्रदेशों के थानों के अंदर सीसीटीवी लगाने का सौ फीसदी खर्च केंद्र सरकार उठाती है। पहाड़ी राज्यों में सीसीटीवी लगाने के लिए 90 फीसदी पैसा केंद्र सरकार देती है जबकि 10 फीसदी राज्य सरकार उठाती है। इसके

अलावा बाकी राज्यों में 60 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार और 40 फीसदी हिस्सा राज्य सरकारें उठाती हैं।

सात अप्रैल को केंद्र सरकार ने कहा था कि वो देश भर के थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से संबंधित सभी मामलों को दो हफ्ते में हल कर लेगी। केंद्र सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा था कि वो खुद इस मामले पर नजर रखे हुए हैं और इस मामले में काफी कुछ प्रगति हुई है। अटार्नी जनरल ने कहा था कि इस मामले में कोर्ट की ओर से नियुक्त एमिकस क्यूरी के साथ दूसरे अधिकारियों की लगातार बैठकें हो रही हैं और इस मामले में काफी कुछ प्रगति हुई है। चार सितंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय ने देश भर के थानों में सीसीटीवी काम नहीं करने के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने कहा था कि 2020 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद थानों में सीसीटीवी काम नहीं कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक अखबार की खबरों पर संज्ञान लिया था। खबर में कहा गया था कि इस साल के सात-आठ महीनों के अंदर पुलिस हिरासत में करीब 11 लोगों की मौत हो चुकी है।

दो दिसंबर 2020 को कोर्ट ने सभी राज्यों को अपने पुलिस स्टेशनों पर ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने आने-जाने वाले द्वार समेत हर अहम स्थानों पर कैमरे लगाने और उसकी रिकॉर्डिंग डेढ़ साल तक संरक्षित रखने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने पुलिस ज्यादती पर रोक लगाने के लिए आदेश दिया था कि देशभर के सभी थानों में सीसीटीवी लगाए जाएं।

ईरान 'ढहने की कगार' पर, होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने को तैयार: ट्रंप

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान इस समय गंभीर संकट से गुजर रहा है और "ढहने की कगार" पर पहुंच चुका है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान ने अमेरिका को संकेत दिया है कि वह कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। जल्द से जल्द हॉर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना चाहता है।

ट्रंप के अनुसार, ईरान फिलहाल अपने आंतरिक नेतृत्व संकट को सुलझाने में लगा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा हालात चुनौतीपूर्ण

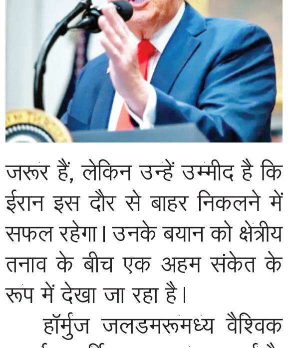

जरूर हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि ईरान इस दौर से बाहर निकलने में सफल रहेगा। उनके बयान को क्षेत्रीय तनाव के बीच एक अहम संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

हॉर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक प्रमुख मार्ग है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से में तेल और गैस का परिवहन होता है। इस मार्ग में बाधा आने से अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर सीधा असर पड़ता है।

हाल के घटनाक्रम में इस जलमार्ग पर आवाजाही प्रभावित होने से ऊर्जा कीमतों में भी उतार-चढ़ाव देखा गया है। इससे पहले, मीडिया रिपोर्ट्स में यह सामने आया था कि ईरान ने युद्ध समाप्त होने और समुद्री नाकेबंदी हटाने की शर्त पर इस जलडमरूमध्य को खोलने का प्रस्ताव दिया था। ऐसे में ट्रम्प का यह बयान इस दिशा में संभावित कूटनीतिक गतिविधियों का संकेत देता है।

माली में हुए आतंकी हमलों की भारत ने की कड़ी निंदा

नई दिल्ली। भारत ने माली में हुए आतंकवादी हमलों की निंदा की है और रक्षा मंत्री जनरल सादियो कामारा सहित पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि माली में कई जगहों को निशाना बनाकर किए गए आतंकवादी हमलों की भारत कड़ी निंदा करता है। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और इस मुश्किल समय में माली की सरकार और वहां के लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाते हैं।

अनिल अंबानी समूह की 3,034 करोड़ की संपत्ति कुर्क

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह (आरएएजी) की कंपनियों के खिलाफ जारी धनशोधन जांच के अंतर्गत 3,034.90 करोड़ रुपये की नई संपत्तियां जब्त की हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को जारी बयान में बताया कि ईडी ने मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 3,034.90 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। एजेंसी के मुताबिक कुर्क की गई संपत्तियों में

मुंबई का एक फ्लैट, खंडाला का फार्महाउस, सानंद की जमीन, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के 7.71 करोड़ शेयर शामिल हैं। इस तरह रिलायंस अनिल अंबानी समूह से जुड़े मामलों में अब तक 19,344 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।

संक्षिप्त खबरें

विद्यालय के स्थापना दिवस पर हवन-पूजन

ग्रेटर नोएडा। समसारा विद्यालय के स्थापना दिवस पर मंगलवार को पूजा पाठ और हवन का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा छठी से आठवीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। बच्चों ने एक समूह गीत भी प्रस्तुत किया। समारोह की शुरुआत में समसारा विद्यालय के संस्थापक ताराचंद शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर समसारा मेरठ पब्लिक स्कूल ऑफ ग्रुप के हेड एडमिन कर्नल प्रमोद कुमार अत्री मौजूद रहे। प्रधानाचार्या डॉक्टर शालिनी प्रसाद ने विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने की सीख दी और सभी को स्थापना दिवस की बधाई दी

सेक्टर-39 और 40 में आज बिजली कटौती

नोएडा। उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति देने के लिए बुधवार को बिजली उपकेंद्रों से निकलने वाली लाइनों की मरम्मत होगी। इसके चलते सुबह दस से शाम पांच बजे तक सेक्टर-39 के बी, ई, एफ, जी और एच ब्लॉक और सेक्टर-40 के ए से एफ ब्लॉक तक आपूर्ति बाधित रहेगी।

सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराया जाएगा

नोएडा। जिले में छह से 14 वर्ष के बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराने के लिए एक मई से विशेष अभियान चलेगा। इसके तहत श्रमिक बस्तियों, ईंट-भट्ठों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को चिह्नित कर विद्यालयों में नामांकित किया जाएगा।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने बताया कि यह अभियान खास तौर पर स्कूल न जाने वाले और बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों पर केंद्रित रहेगा। दिव्यांग बच्चों को भी स्पेशल एजुकेटर के सहयोग से चिह्नित कर उनका नामांकन कराया जाएगा। पढ़ाई छोड़ चुकी बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिलाया जाएगा। इसे लेकर सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिए गए हैं। पहचान की प्रक्रिया शुरूअभियान के प्रथम चरण में ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। दूसरे चरण में इसे और तेज कर छूटे हुए बच्चों तक सीधी पहुंच बनाई जाएगी। आरटीई के अंतर्गत निजी विद्यालयों में लॉटरी के माध्यम से चयनित बच्चों का शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित कराने पर भी विशेष जोर दिया गया है। वहीं, विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए आपरेशन कायाकल्प और प्रोजेक्ट अलंकार के तहत व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं।

घर का ताला तोड़कर सोने के गहने चुराए

ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र की गोविंद एन्क्लेव कॉलोनी में बदमाशों ने एक घर का ताला तोड़कर सोने के गहने चोरी कर लिए। पीड़ित घटना के समय ड्यूटी पर गया था। इसी बीच बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। सूरजपुर कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गोविंद एन्क्लेव में पुनीत कुमार रहते हैं। वह दस अप्रैल को घर पर ताला लगाकर रात में ड्यूटी गए थे। इसी बीच बदमाशों ने मौका पाकर ताला तोड़कर अलमारी में रखी सोने की दो चेन और एक अंगूठी आदि सामान चोरी कर लिया। वह सुबह घर पहुंचे तो चोरी का पता चला। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बदमाशों की तलाश की जा रही है।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 16 गांवों में लाइटें लगेंगी

ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट के बिसरख ऐमनाबाद, सादोपुर, छपरौला समेत 16 गांवों की सभी गलियां एलईडी स्ट्रीट लाइट से जगमग होंगी। अंधेरे वाली गलियों में ये लाइट लगाने के लिए निविदा जारी कर कंपनियों से आवेदन मांगे गए हैं। फर्म का चयन कर एक महीने में काम शुरू करने की तैयारी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में शहरी क्षेत्र के साथ आसपास के गांवों का भी तेजी से विस्तार हुआ है। नई बसावट वाले इलाके में स्ट्रीट लाइट का काम अधूरा होने की वजह से अंधेरा रहता है। लोगों की परेशानी को देखते हुए प्राधिकरण के विद्युत अभियांत्रिकी विभाग ने सभी गलियों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने की कार्ययोजना तैयार की है। ग्रेटर नोएडा ईस्ट इलाके के गांवों में भी स्ट्रीट लाइट का काम बाकी बचा है। वहां भी काम पूरा कराया जाएगा।

आग से चारा जलकर राख, ग्रामीणों ने पाया आग पर काबू

दनकौर। नवादा गांव में सोमवार देर रात तेज आंधी में लगी आग से चारा जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जयकिशन ने अपने खेत में सूखा चारा भूसा रखा था। सोमवार रात अचानक तेज आंधी चली। इस दौरान किसी तरह चिंगारी भूसे के ढेर में गिरने से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे ढेर को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद कई घंटे बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पीड़ित किसान जय किशन ने बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही यह चारा तैयार किया था। आग लगने के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। पीड़ति किसान ने क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजे की मांग प्रशासन की है।

पत्नी को पीटकर बेहोश किया

नोएडा। छलेरा गांव में पति ने मारपीट कर पत्नी को बेहोश कर दिया। महिला का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। उसकी शिकायत पर सेक्टर-39 थाने की पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। छलेरा गांव निवासी पूजा चौहान ने सेक्टर-39 थाने में शिकायत दी कि पति धमेंद्र चौहान रविवार को रात ढाई बजे घर पर शराब पीकर आए। नशे में उन्होंने उसके साथ मारपीट की। उन्होंने उसको थप्पड़ मार मारकर बेहोश कर दिया। किसी तरह महिला ने अपनी जान बचाई। मारपीट के बाद धर्मेंद्र ने पत्नी से कहा कि अगर उसने मामले की शिकायत पुलिस से की तो उसे जान से मार देगा। पुलिस केस दर्ज करने के बाद आरोपी की तलाश कर रही है। महिला का कहना है कि शराब के नशे में पति पहले भी उसके साथ मारपीट कर चुका है।

स्कूल के समय में कटौती से नाराज अभिभावक जिलाधिकारी से मिले

बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की जताई चिंताएं

नोएडा। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही स्कूलों के समय में की गई कटौती को लेकर अभिभावकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी मुद्दे को लेकर अभिभावकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम से मुलाकात कर अपनी समस्याएं और चिंताएं उनके सामने रखीं।

अभिभावकों ने बताया कि जहां पहले स्कूल दोपहर 2 से 2:30 बजे तक संचालित होते थे, वहीं प्रशासन के आदेश के बाद अब समय घटाकर दोपहर 12 बजे तक कर दिया गया है। उनका कहना है कि पहले ही साल भर में त्यौहारों, गर्मी और सर्दी की छुट्टियों के साथ-साथ शनिवार और रविवार के कारण पढ़ाई के दिन सीमित रह जाते हैं। ऐसे में बार-बार स्कूल बंद होने या समय में कटौती से बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि सर्दियों में प्रदूषण, कोहरा और शीतलहर के कारण तथा बरसात और गर्मियों में मौसम के चलते स्कूलों को बंद कर दिया जाता है या समय घटा दिया जाता है। इससे स्कूलों पर कम समय में पाठ्यक्रम पूरा करने का दबाव बनता है, जो अंततः बच्चों और अभिभावकों पर पड़ता है। अभिभावकों ने निजी स्कूलों की ऊंची फीस का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना था कि कई निजी स्कूल सालाना 5 से 6 लाख रुपये तक फीस लेते हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड एसी से लैस है। ऐसे में बच्चे सुरक्षित माहौल में पूरे समय पढ़ाई कर सकते हैं।

इसके बावजूद अचानक समय में बदलाव या स्कूल बंद करने के फैसले से अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि नोएडा में अधिकांश परिवारों में दोनों अभिभावक कार्यरत हैं, ऐसे में स्कूलों की अचानक छुट्टी या समय में बदलाव से बच्चों की देखभाल को लेकर अतिरिक्त कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं।

गर्मी की छुट्टियों में पहाड़ों के लिए नोएडा से चलेंगी अतिरिक्त बसें

नोएडा। गर्मी की छुट्टियों के दौरान पहाड़ों की ओर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए नोएडा डिपो से अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार और हल्द्वानी के लिए दो-दो अतिरिक्त बसें रवाना करने का फैसला लिया है। नोएडा डिपो से पहले से ही हरिद्वार, देहरादून और कोटद्वार के लिए बसें संचालित हो रही हैं, जबकि हल्द्वानी जाने वाले यात्री लालकुआं तक डिपो की बसों से यात्रा कर सकते हैं।

गर्मी की छुट्टियों में इन गंतव्यों की ओर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसों का प्रबंध किया गया है। यात्री अपनी सीट पहले से पक्की करने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.upsrtc.up.gov.in पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। जिले के अधिकांश निजी स्कूलों में मई के तीसरे सप्ताह से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। ऐसे में नोएडा और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों की सैर करने जा रहे हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, कोटद्वार और नैनीताल पर्यटकों की पसंदीदा जगहें बनी हुई हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि हरिद्वार और कोटद्वार के लिए प्रतिदिन चार से पांच बसें चलाई जा रही हैं, जबकि देहरादून और हल्द्वानी (लालकुआं) के लिए एक-एक बस है। आवश्यकता पड़ने पर ऋषिकेश के लिए भी बसों की व्यवस्था की जाएगी।

सभी बसें साधारण और सीएनजी चालित हैं। उन्होंने कहा कि बसों में ट्रेन की तरह सीट न मिलने की समस्या नहीं होती है, इसलिए गर्मी की छुट्टियों में बड़ी संख्या में यात्री बस यात्रा को प्राथमिकता देते हैं। पिछले वर्षों के अनुभव को देखते हुए इस बार अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो में कुल 305 बसें हैं, जिनमें नोएडा डिपो में 188 बसें शामिल हैं। इन बसों से प्रतिदिन औसतन 40 से 45 हजार यात्री यात्रा करते हैं। डिपो में वातानुकूलित बसों की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वातानुकूलित बसों से यात्रा करने वाले यात्री कौशांबी, आनंद विहार या कश्मीरी गेट बस अड्डे से बस पकड़ सकते हैं। यह व्यवस्था गर्मी की छुट्टियों के दौरान नोएडा से पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा करने वाले लोगों के लिए राहत भरी साबित होने की उम्मीद है।

घुड़चढ़ी में डीजे बजाने पर परिवार का सामाजिक बहिष्कार

दनकौर। नवादा गांव में पंचायत के फैसले की अनदेखी एक परिवार पर भारी पड़ गई। पंचायत ने घुड़चढ़ी में डीजे बजाने पर मंगलवार को गांव के एक व्यक्ति और उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। पंचायत के इस फैसले के बाद पूरे गांव में मुनादी कराकर ग्रामीणों को डीजे बजवाने वाले व्यक्ति के परिवार के सामाजिक बहिष्कार के निर्णय की जानकारी दी गई।

नवादा गांव में एक महीने पहले हुई पंचायत में सर्वसम्मति से तय किया गया था कि गांव में शादी समारोहों में डीजे नहीं बजवाया जाएगा। पंचायत का कहना था कि डीजे के कारण ध्वनि प्रदूषण के साथ गांव की सामाजिक व्यवस्था और परंपराएं प्रभावित होती हैं। इस कारण ही गांव की पंचायत ने सामूहिक सहमति से डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बावजूद गांव के राजीव नागर ने पंचायत के फैसले को नजरअंदाज कर सोमवार रात अपने दो बेटों की घुड़चढ़ी और बारात की चढ़त के दौरान जमकर डीजे बजवाया। इसके बाद गांव के लोग नाराज हो गए। पंचायत में निर्णय लेने वाले पंचों को भी यह बात नागवार गुजरी।

इस मामले को लेकर मंगलवार को दोबारा पंचायत बुलाई गई, जिसमें पूर्व प्रधानाचार्य नरपत नागर, ग्राम प्रधान राजे सिंह नागर समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पंचायत में कहा गया कि जब गांव ने सामूहिक रूप से एक नियम बनाया था तो उसका पालन करना चाहिए था। गांव वालों का तर्क था कि पंचायत के निर्णय की अवहेलना गांव की एकता और सामाजिक अनुशासन के खिलाफ है। लंबी चर्चा और बहस के बाद पंचायत ने सर्वसम्मति से राजीव नागर और उनके परिवार के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय लिया। पंचायत ने साफ किया कि अब गांव का कोई भी व्यक्ति राजीव नागर के परिवार को शादी-विवाह या अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में निमंत्रण नहीं देगा और न ही उनके यहां आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होगा। पंचायत ने यह भी चेतावनी दी कि जो ग्रामीण इस फैसले का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।

पंचायत में धीरज प्रमुख, बालकिशन प्रधान, राज सिंह प्रधान, मोहन बीडीसी, संजय नवादा, चंदी सिंह, त्रिलोक नागर, चंद्रपाल सिंह, मिश्री, जयपाल मुखिया, ओमकार, नीरज सरपंच, रामी, महेश, मास्टर, अशोक नागर, जगत, जसराज, रुग्गन, विक्रम मास्टर और राजू समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।

सीआईएससीई जोनल एथलेटिक मीट में बेटियों ने दिखाया दमखम

बालिका वर्ग के मुकाबले में 14 विद्यालयों से 182 छात्राओं ने भाग लिया

ग्रेटर नोएडा। सेक्टर अल्फा-1 स्थित सेंट जोसेफ विद्यालय में हुई दो दिवसीय सीआईएससीई जोनल एथलेटिक मीट में मंगलवार को बालिका वर्ग में मुकाबले हुए। प्रतियोगिता में गाजियाबाद क्षेत्र के लगभग 14 विद्यालयों से 182 छात्राओं ने भाग लिया और अंडर-14, अंडर-17 एवं अंडर-19 आयु वर्ग में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। स्कूल के प्रधानाचार्य फादर जिप्सन पलाटी ने बताया कि दूसरे दिन बालिका वर्ग में मुकाबले हुए।

अंडर-14, 17 व 19 वर्ग में खिलाड़ियों ने दौड़, लंबीकूद, ऊंचीकूद, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो आदि स्पर्धाओं में खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। अंडर-14 की लंबी कूद में पहले नंबर पर होली चाइल्ड विद्यालय की सौम्या यादव, दूसरे नंबर पर सेंट जोसेफ अकादमी की दृष्टि शर्मा और तीसरे पर अंशिका यादव रहीं। अंडर-17 कदम चाल में जानवी शर्मा (इंग्राहम विद्यालय) पहले, वंशिका त्यागी (माउंट कैरेमल विद्यालय) दूसरे और निशा यादव (जीसस एंड मैरी विद्यालय) दूसरे स्थान पर रहीं। 1500 मीटर दौड़ में इंग्राहम विद्यालय की नव्या शर्मा ने बाजी मारी जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः रिया चौहान (क्रिस्टी ज्योति विद्यालय) और मान्या कुमारी (इंग्राम विद्यालय) रहीं। लंबी कूद में सेंट जोसेफ अकादमी की उन्नति त्यागी पहले, सेंट जोसेफ विद्यालय की रेचल इक्का और हिमाक्षी सिंह दूसरे और तीसरे नंबर पर रहीं। डिसक्स थ्रो में सेंट जोसेफ अकादमी की शुभांगी शर्मा अव्वल रहीं।

श्समाउंट कार्मल अकादमी की अनुष्का चौधरी दूसरे और होली एंगल विद्यालय की आंशिक सिंह तीसरे पायदान पर रहीं। अंडर-19 में 1500 मीटर दौड़ अनन्या कश्यप पहले, रिद्धिमा पंकज दूसरे, दिशइता गोला तीसरे नंबर पर रहीं। 400 मीटर दौड़ में दीक्षा पांडेय प्रथम, अदिति जयंत द्वितीय और अभिका त्यागी तृतीय रहीं।

सुपरटेक ईको विलेज-1 में मेंटेनेंस स्कीम को लेकर विवाद

ग्रेटर नोएडा, 28 ग्रेनो वेस्ट स्थित सुपरटेक ईको विलेज-1 में मार्च 2025 में लागू हुई मेंटेनेंस स्कीम को लेकर विवाद हो गया है। स्कीम के तहत भुगतान करने वाले निवासियों ने आरोप लगाया है कि घोषित लाभ अब लागू नहीं किए जा रहे हैं। मार्च 2025 में लाई गई बिजली मीटर मेंटेनेंस की इस स्कीम में 11 महीने का अग्रिम भुगतान करने पर 1 महीने की छूट देने का प्रावधान था। इस पर कई निवासियों ने एस्क्रो खाते में भुगतान किया था। निवासियों का कहना है कि अगस्त 2025 में प्रबंधन के बदलने के बाद स्कीम पर मिलने वाले लाभ रोक दिए गए। ईको विलेज-1 सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि स्कीम को लेकर स्पष्टता नहीं दी जा रही है और निवासियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। निवासियों के प्रतिनिधि अरुण गुप्ता ने कहा कि भुगतान के बाद स्कीम के लाभ नहीं मिले। कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं निकाला गया।

संपूर्ण भुगतान कर खरीदी कार, फर्जीवाड़ा कर दर्शाया ऋण

नोएडा। सेक्टर-24 थाना क्षेत्र स्थित कार कंपनी के डीलर के यहां फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। ग्राहक ने संपूर्ण भुगतान कर कार खरीदने का दावा किया है। उसने कंपनी के अधिकारियों और बैंक प्रबंधन पर फर्जीवाड़ा करके कार पर ऋण दर्शाने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश कर दिए हैं।

नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के बादौली बांगर गांव निवासी अतेंद्र कुमार ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके पास नामी कंपनी की कार है। यह कार उनके भाई भरत सिंह ने वर्ष 2019 में अधिकृत डीलर से खरीदी थी। खरीदने के समय संपूर्ण भुगतान किया था। उस समय किसी बैंक या किसी अन्य संस्था से कोई आर्थिक मदद नहीं ली गई थी। आरोप है कि कार कंपनी के अधिकारियों ने बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कराए, जिन पर शिकायतकर्ता के भाई के फर्जी हस्ताक्षर किए गए। कार पर गैर कानूनी और गलत तरीके से ऋण दर्शाया गया।

कुछ समय पूर्व भरत सिंह ने जब कार को बेचने का प्रयास किया तो सत्यापन के दौरान पता चला कि कार पर ऋण लिया हुआ है। यह देख शिकायतकर्ता और उनके भाई को झटका लगा। आरोप है कि कार कंपनी के अधिकारियों ने एनओसी जारी करने की एवज में अवैध रूप से पांच लाख रुपये की मांग की। न्यायालय ने सेक्टर-24 थाना पुलिस को आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ पर्यावरण, स्वास्थ्य और नीति पर मंथन

ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से आयोजित दो-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन "द नेक्सस इम्पेरेटिव: एनवायरनमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर" का भव्य उद्घाटन किया गया। यह सम्मेलन पर्यावरण, जनस्वास्थ्य और नीतिगत ढांचों के बीच संबंधों पर गंभीर विमर्श के लिए देशभर के शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और नीति-निर्माताओं को एक मंच प्रदान कर रहा है।

उद्घाटन सत्र में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राणा प्रताप सिंह ने मुख्य संरक्षक के रूप में अध्यक्षता की। इस अवसर पर पूर्व मुख्य सचिव झारखंड सुधीर त्रिपाठी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि मुख्य अतिथि मेजर जनरल गगनदीप बख्शी ने अपने संबोधन में पर्यावरणीय सुरक्षा को राष्ट्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण और जनस्वास्थ्य संकट आज के उभरते गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरे हैं, जिनसे निपटने के लिए सशक्त नीतिगत समन्वय और संस्थागत तैयारी आवश्यक है। कुलपति प्रो. राणा प्रताप सिंह ने अपने विचारों में विश्वविद्यालयों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि शोध और नीति के बीच सेतु निर्माण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने अंतःविषयक अनुसंधान, नवाचार आधारित समाधान और साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेपों पर जोर दिया, ताकि जटिल पर्यावरणीय और स्वास्थ्य चुनौतियों का प्रभावी समाधान निकाला जा सके। अपने संबोधन में सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि पर्यावरणीय नीतियों की सफलता उनके प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी और जनभागीदारी पर निर्भर करती है। उन्होंने प्रशासनिक तंत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकें। कार्यक्रम में प्रो. प्रतीक शर्मा की उपस्थिति ने भी सम्मेलन को विशेष बनाया।

उन्होंने तकनीकी नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा आधारित दृष्टिकोण को पर्यावरणीय शासन और जनस्वास्थ्य सुधार के लिए महत्वपूर्ण बताया। वहीं प्रवीण रामदास ने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय को सतत विकास की दिशा में आवश्यक बताया। उद्घाटन सत्र के दौरान सम्मेलन स्मारिका का भी विमोचन किया गया, जिसमें सम्मेलन की अवधारणा, विशिष्ट अतिथियों के संदेश और शोध-पत्रों के सार शामिल हैं। यह सम्मेलन विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग, स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज एंड एप्लाइड साइंसेज द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

दो दिवसीय इस सम्मेलन में तकनीकी सत्र, पैनल चर्चाएँ और शोध प्रस्तुतियाँ आयोजित की जा रही हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, जनस्वास्थ्य चुनौतियाँ और सतत नीतिगत हस्तक्षेप जैसे विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श हो रहा है। देशभर से आए प्रतिभागी विज्ञान और नीति के बीच मजबूत समन्वय स्थापित करने की दिशा में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं।

महिला आरक्षण पर अब याचना नहीं, रण होगा : रेखा गुप्ता

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा के विशेष सत्र में कहा कि केंद्र सरकार ने विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' पारित किया था। इसके लिए 131वां संविधान संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किया ताकि महिलाओं को जल्द लाभ मिल सके।

लेकिन 16, 17 और 18 अप्रैल के दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक दुखद अध्याय के रूप में दर्ज हुए हैं। इन दिनों पूरे देश की महिलाएं लोकसभा की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही थीं कि 78 वर्षों का लंबा इंतजार अब समाप्त होगा और उन्हें विधानसभाओं तथा लोकसभा में प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा। लेकिन इन दिनों हुई चर्चाओं ने निराशा ही दी। मुख्यमंत्री ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के दौरान कहा कि अब समय आ गया है कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए स्वयं खड़ी हों। अब याचना नहीं, रण होगा और महासंग्राम भीषण होगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से महिलाएं देख रही हैं कि विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं द्वारा केवल दिखावे और षड्यंत्र किए गए हैं, लेकिन न्याय सुनिश्चित नहीं किया गया। देश की महिलाएं अब अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं और पूरे देश में एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही हैं। अब हर दिशा से एक ही आवाज उठ रही है कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' लागू होना चाहिए और यह होकर रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि महिलाओं को सामाजिक बाधाओं और चुनौतियों का सामना पुरुषों की तुलना में अधिक करना पड़ता है। ऐसे में केवल अधिकार नहीं, बल्कि विशेष प्रावधान ही समान अवसर सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने बताया कि आरक्षण और जनसमर्थन के जरिए ही उन्हें जनसेवा का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि पंचायत व स्थानीय निकायों में बड़ी संख्या में महिलाएं चुनी जाती हैं, लेकिन विधानसभा और संसद तक उनकी भागीदारी काफी कम रह जाती है। देश में लगभग 4600 विधायकों में केवल 10 प्रतिशत

महिलाएं हैं और लोकसभा-राज्यसभा में भी उनकी हिस्सेदारी करीब 13-14 प्रतिशत ही है, जो अवसरों की कमी को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार और चुनाव का अवसर तो दिया, पर केवल इससे वे आगे नहीं बढ़ सकीं और उन्हें राजनीतिक अवसरों से वंचित रखा गया। उन्होंने बताया कि महिला आरक्षण विधेयक 27 वर्षों में सात बार संसद में आया, लेकिन हर बार रोका गया। कई दलों ने बाधाएं खड़ी कीं और महिलाओं को सीमित भूमिका में रखा, जबकि भाजपा ने उन्हें आगे बढ़ने के अवसर दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' लाया गया, जो महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था।

इसके क्रियान्वयन में तकनीकी प्रक्रियाओं, जैसे परिसीमन आदि के कारण समय लगने की संभावना को देखते हुए, सरकार ने इसे शीघ्र लागू करने के उद्देश्य से आवश्यक संशोधनों का प्रस्ताव रखा। लेकिन विपक्षी दलों ने इस दिशा में भी आपत्तियां उठाकर और तकनीकी मुद्दों को आधार बनाकर इस विधेयक को पारित होने से रोकने का प्रयास किया। यह स्पष्ट रूप से महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखने का प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विषय केवल एक विधेयक का नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी के अधिकार और सम्मान का है।

किसी भी पुरुष प्रतिनिधि के लिए अपनी सीट छोड़कर महिला को स्थान देना सहज निर्णय नहीं होता। इसी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रारूप प्रस्तावित किया गया, जिसमें सीटों की संख्या बढ़ाकर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सके। इस व्यवस्था से क्षेत्रीय दलों को भी लाभ होता और दक्षिण भारत के राज्यों की सीटों पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि यह समझ से परे है कि इस प्रस्ताव में विपक्ष को आपत्ति किस बात पर थी, जबकि इसमें सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखा गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि कि ओबीसी महिलाओं के संदर्भ में 'कोटे में कोटा' की मांग भी केवल बहाने के रूप में प्रस्तुत की गई, जबकि पूर्व में इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई।

विभिन्न तकनीकी और राजनीतिक मुद्दों को आधार बनाकर इस विधेयक को टालने का प्रयास किया गया, जबकि मूल उद्देश्य केवल महिलाओं को उनका अधिकार दिलाना था। आज महिलाओं के नाम पर केवल मुद्दों को उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। कभी 543 सीटों की बात, कभी 850 सीटों की, कभी परिसीमन की, कभी क्षेत्रीय संतुलन की। इस विधेयक के पारित न होने के बाद जिस प्रकार कुछ दलों द्वारा उत्सव मनाया गया, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी (आआपा) की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि 'सत्याग्रह' जैसे पवित्र शब्द का दुरुपयोग करते हुए न्यायिक प्रक्रिया से बचने की बात करना गलत है। महात्मा गांधी की विचारधारा का इस तरह इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है और कानून से ऊपर खुद को रखना गंभीर विरोधाभास दर्शाता है। जब न्याय देने वाली महिला न्यायाधीश होती हैं तो कुछ लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाते, जो महिला-विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। यह सब अपने कृत्यों के उजागर होने के डर को दिखाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे व्यवहार से सदन की कार्यवाही भी प्रभावित होती है और यह 'मेरी मर्जी' वाली मानसिकता को दर्शाता है, जहां व्यक्ति खुद को कानून से ऊपर समझकर न्यायिक प्रक्रिया से बचने की कोशिश करता है।

कोई व्यक्ति खुद ही मुजरिम, गवाह, वकील और न्यायाधीश बनने लगे, यह लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्याय केवल न्यायपालिका ही करेगी। उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह किया गया है और किए गए कार्यों का परिणाम जरूर सामने आएगा। साथ ही, उन्होंने सुश्री आतिशी के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि जिस परिस्थितियों में वे काम कर रही हैं, वे कठिन हैं और उनका वक्तव्य न दे पाना भी संभवतः किसी कारणवश हुआ है।

संक्षिप्त खबरें

कमानी ऑडिटोरियम में तीन दिन चलेगा नृत्य उत्सव

नई दिल्ली। कमानी ऑडिटोरियम में श्रीराम भारतीय कला केंद्र की ओर से एक से तीन मई तक नृत्य उत्सव का आयोजन होगा। हर दिन शाम सात बजे शुरू होने वाला यह तीन दिवसीय उत्सव भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य परंपराओं का संगम पेश करेगा। तीन प्रमुख नृत्य-नाटिकाएं प्रस्तुत होंगी। इनमें छऊ, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी और कथकली जैसी शास्त्रीय शैलियों के साथ लोक नृत्यों का भी समावेश होगा। आकर्षक संगीत, परिधान, साज-सज्जा और लाइटिंग इस फेस्टिवल को खास बनाएंगे। ये कार्यक्रम होंगे- पहले दिन चक्रव्यूह में महाभारत के अभिमन्यु की वीरता और युद्ध की जटिलता को मंच पर जीवंत किया जाएगा।- दूसरे दिन श्री दुर्गा के जरिए देवी दुर्गा और काली के रूपों को दर्शाते हुए महिषासुर और रक्तबीज वध की कथा दिखाई जाएगी। तीसरे दिन कार्तिकेय प्रस्तुति में भगवान शिव-पार्वती, गणेश और कार्तिकेय से जुड़ी पौराणिक कथाओं को आधुनिक अंदाज में पेश किया जाएगा।

भारत मंडपम में भारत-अफ्रीका संबंधों को लेकर हुई चर्चा

नई दिल्ली। भारत मंडपम में मंगलवार को आयोजित युवा भारत ग्लोबल फोरम में भारत-अफ्रीका संबंधों को और सशक्त बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। चकबाल समूह की तरफ से आयोजित इस फोरम में विभिन्न देशों के राजदूतों, वरिष्ठ अधिकारियों, थिंक टैंक प्रतिनिधियों, उद्योग संगठनों और मीडिया के सदस्यों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने शिरकत की। मंत्री मार्गेरिटा ने कहा, कि भारत-अफ्रीका संबंध एक निर्णायक और परिवर्तनकारी दौर में प्रवेश कर रहे हैं। यह साझेदारी सदियों पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित है, जिसे व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और औपनिवेशिक दौर के साझा संघर्षों ने और मजबूत किया है। उन्होंने विकसित भारत 2047 और अफ्रीका के एजेंडा 2063 के बीच समानताओं का उल्लेख करते हुए कहा, कि दोनों ही दृष्टिकोण समावेशी और सतत विकास पर केंद्रित हैं। फोरम के दौरान अंगोला, केन्या, इथियोपिया, सूडान सहित कई अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

करियर काउंसलिंग फेयर में छात्रों को मिलेगा मार्गदर्शन

नई दिल्ली। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से एक और दो मई को गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब परिसर स्थित भाई लखी शाह वणजारा हॉल में करियर काउंसलिंग फेयर आयोजित किया जाएगा। कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।

दिल्ली के उपराज्यपाल संधू ने ग्रीष्मकालीन कार्ययोजना को लेकर की गहन समीक्षा

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली में भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने मंगलवार को पालिका केंद्र स्थित एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) का उच्चस्तरीय दौरा किया।

इस दौरे का मुख्य उद्देश्य ग्रीष्मकालीन कार्य योजना और लू से निपटने के लिए लागू किए गए मौजूदा उपायों की गहन समीक्षा करना था। इस दौरान उपराज्यपाल संधू ने एक्स पर कहा कि जैसे-जैसे हम 'विकसित भारत' की ओर बढ़ रहे हैं दिल्ली की भूमिका केंद्रीय बनी हुई है और दिल्ली इसी परिकल्पना का प्रतीक है।

हमारी वास्तविक प्राथमिकता जमीनी स्तर पर मजबूत क्रियान्वयन होनी चाहिए ताकि कमजोर समुदायों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हम एक सुदृढ़ और नागरिक-केंद्रित शहरी शासन को समर्थन देने और उसे मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि राजधानी के डिजिटल तंत्रिका केंद्र के रूप में आईसीसीसी सेवाओं को एकीकृत करने के लिए आईओटी-आधारित प्रणालियों का उपयोग करता है। इसमें जल प्रबंधन से लेकर पर्यावरण निगरानी तक शामिल है।

शासन के इस प्रौद्योगिकी-सक्षम मॉडल में पूरे देश के शहरी स्थानीय निकायों में दोहराए जाने की क्षमता है, जिससे नागरिक सेवाओं की डिलीवरी में सुधार हो सके।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वालों को इतिहास माफ नहीं करेगा : सिरसा

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक) पर चर्चा के दौरान पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह विधेयक देश की आधी आबादी को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने का ऐतिहासिक प्रयास था।

उन्होंने कहा कि लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषदों में महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम था, लेकिन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, डीएमके और अन्य विपक्षी दलों ने मिलकर इस ऐतिहासिक अवसर को बाधित करने का कार्य किया। सिरसा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य किया है। पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण के माध्यम से लाखों महिलाएं आज निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनी हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास के क्षेत्र में प्रभावी नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक महिला सहभागिता मॉडल का उदाहरण है। सिरसा ने कहा कि देश की 50 प्रतिशत आबादी को उनका अधिकार देने के लिए प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाये।

यदि यह विधेयक पूर्ण रूप से लागू होता, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत हमारी बहन-बेटियां निर्णय लेने वाली भूमिका में होतीं। यह केवल आरक्षण नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करने का कदम था। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक के ऐतिहासिक संदर्भ को रखते हुए कहा कि 1996 से लेकर 2010 तक कई बार इस विधेयक को आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ, लेकिन कांग्रेस ने बार-बार इसे रोकने का काम किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भी चार बार इसे सदन में लाने का प्रयास किया, परंतु विपक्ष के विरोध के कारण यह सफल नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि 2010 में राज्यसभा से विधेयक पारित होने के बाद देश की महिलाओं को उम्मीद जगी थी, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने उसे लोकसभा तक पहुंचने नहीं दिया।

2023 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसे फिर आगे बढ़ाया, तब भी विपक्ष ने हिचकिचाहट और राजनीतिक स्वार्थ के साथ इसका विरोध किया। सिरसा ने कहा कि यदि 131वें संविधान संशोधन के माध्यम से सीटों का विस्तार और 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित होता, तो लोकसभा में 200 से अधिक महिलाएं प्रतिनिधित्व करतीं और देशभर में महिला नेतृत्व का एक नया अध्याय शुरू होता।

स्वाति मालीवाल ने भाजपा में शामिल होने की औपचारिकता पूरी की

नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद एवं दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने की औपचारिकता पूरी की। दिल्ली भाजपा कार्यालय में स्वाति मालीवाल ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा और सांसद योगेन्द्र चंदोलिया की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

मालीवाल ने कहा कि आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। मैं भावुक भी हूं, आज भाजपा में शामिल होने का मौका मिला।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से प्रेरणा लेकर मैं भाजपा में जुड़ी हूं। भाजपा के कार्यों में मुझे बहुत पहले से दिलचस्पी रही है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर रहने के दौरान भाजपा की तरफ से काफी सहयोग मिला था। मैं दिल्ली के लिए अब और जी-जान से काम करूंगी, जैसे हमेशा से करती आई हूं।

आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आआपा पूरे देश में ड्रामा, झूठ, फ़रेब, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार इसके लिए जानी जा रही है, जो बहुत शर्म की बात है। पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आआपा के संयोजक केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा लूट मचा रखी थी। बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर रखा था।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया केजरीवाल पर पाखंड का आरोप

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर गांधीवादी विचारधारा के नाम पर 'पाखंड' करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पहले कार्यालयों से महात्मा गांधी की तस्वीरें हटाने वाले अब सत्याग्रह की बात कर रहे हैं।

देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि दिल्ली और पंजाब में सरकार बनने के बाद कार्यालयों से महात्मा गांधी की तस्वीरें हटाई गईं, जबकि अब वही नेतृत्व गांधी के मूल्यों का पालन करने का दावा कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह जनता को गुमराह करने की कोशिश है। उन्होंने आबकारी नीति मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान किए बिना अदालत में पेश न होना उचित नहीं है। इस संदर्भ में मनीष सिसोदिया का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मामले में जिम्मेदार नेताओं को कानून का पालन करना चाहिए। देवेंद्र यादव ने कहा कि राजघाट जाकर सत्याग्रह की बात करने से भ्रष्टाचार के आरोप खत्म नहीं होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए कई गंभीर मामलों को जन्म दिया गया, जिसके कारण जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि एक राजनीतिक दल के प्रमुख होने के नाते अरविंद केजरीवाल को न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए और राजनीतिक लाभ के लिए सत्याग्रह का सहारा नहीं लेना चाहिए।

इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय का 'समन्वय 2026' समारोह संपन्न

नई दिल्ली। इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय का वार्षिक पुरस्कार समारोह 'समन्वय 2026' उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन महाविद्यालय की प्रतिभा, उपलब्धियों और उत्कृष्टता का उत्सव रहा, जिसमें छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों और विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में महाविद्यालय की समृद्ध विरासत की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान लगातार ऐसे युवा तैयार कर रहा है, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सार्थक योगदान दे रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए छात्राओं को बदलती दुनिया में 'क्रिटिकल थिंकिंग' और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित

किया। साथ ही, उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की बढ़ती भूमिका और भविष्य में इसके प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के डीन ऑफ कॉलेजेज प्रो. बलराम पाणी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. पूनम कुमरिया ने की। उन्होंने अपने संबोधन में संस्थान की मजबूत शैक्षणिक परंपरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किए जा रहे नवाचारों और विभिन्न सहयोगों की जानकारी दी।

उन्होंने परिसर में सततता, छात्र कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों को भी रेखांकित किया। समारोह का एक प्रमुख आकर्षण महाविद्यालय की नई आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ रहा, जिसे शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और सुगम बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। कार्यक्रम के दौरान इनेबलिंग यूनिट की छात्राओं सहित कुल 73 विद्यार्थियों को शैक्षणिक और सह-पाठ्यक्रम क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।

सफदरजंग अस्पताल में हीट स्ट्रोक यूनिट सक्रिय

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ती गर्मी और संभावित लू को देखते हुए सफदरजंग अस्पताल ने हीट से जुड़ी बीमारियों से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी करते हुए विशेष 'हीट स्ट्रोक यूनिट' को फिर से सक्रिय कर दिया है। इस केंद्र में लू से प्रभावित मरीजों को त्वरित और प्रभावी उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। अस्पताल प्रशासन ने मंगलवार को बताया कि इस यूनिट को अस्पताल के न्यू इमरजेंसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर स्थापित किया गया है जहां कुल 7 बेड आरक्षित किए गए हैं। इनमें से 2 बेड ईआर-1 में और 5 बेड ईआर-4 में स्थित हैं। यहां ट्रायेज के माध्यम से मरीज सीधे पहुंच सकते हैं, जिससे इलाज में देरी न हो। हीट स्ट्रोक, हीट एक्सॉशन और डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर स्थितियों से निपटने के लिए मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, एनेस्थीसिया और कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों की समर्पित टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही आवश्यक दवाइयों, कूलिंग उपकरणों और आपातकालीन प्रबंधन की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार फिलहाल यहां हीट से संबंधित किसी भी मरीज की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन सतर्कता के तौर पर सभी इंतजाम पूरी तरह सक्रिय रखे गए हैं। विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि वे पर्याप्त पानी पीएं और धूप से बचे।

उत्तर रेलवे

इ-निविदा (इ-प्रोक्यूर्मेंट) के माध्यम से निविदा आमंत्रण

निम्नलिखित कार्य के लिये वरिष्ठ मंडल अभियंता/II, उत्तर रेलवे, दिल्ली मंडल में ई-निविदा आमंत्रण।

1	NIT-04	**कार्य का नामः**- वरिष्ठ मंडल अभियंता-II के अंतर्गत सहायक मंडल अभियंता मेरठ के कार्य क्षेत्र में भिन्न जगह पर सेस रिपेयर कार्य का प्रावधान। **कार्य की अनुमानित लागत (रूपये) :-** 24310363.84 **बयाना राशि (रूपये) :-** 486200.00
2	NIT-07	**कार्य का नामः**- वरिष्ठ मंडल अभियंता-II के अंतर्गत सहायक मंडल अभियंता गाजियाबाद के कार्य क्षेत्र स्थित इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेंटर का उन्नयन आदि कार्य का प्रावधान। **कार्य की अनुमानित लागत (रूपये) :-** 9390305.87 **बयाना राशि (रूपये) :-** 187800.00
3	NIT-09	**कार्य का नामः**- वरिष्ठ मंडल अभियंता-II के अंतर्गत सहायक मंडल अभियंता मेरठ के कार्य क्षेत्र में यार्ड सुधार कार्य का प्रावधान। **कार्य की अनुमानित लागत (रूपये) :-** 42921464.94 **बयाना राशि (रूपये) :-** 858400.00
2	**निविदा खोलने की तिथि और समय**	19.05.2026 15:00 Hrs.
3	**वेबसाइट विवरण जहां निविदा दस्तावेजों का पूरा विवरण देखा जा सकता है**	निविदा www.ireps.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध।

- ठेकेदारों को ई-टेण्डर प्रणाली में भाग लेने के लिए भारतीय रेलवे ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम) IREPS) साइट यानी **www.ireps.gov.in** के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
- सभी नियमों और शर्तों के लिए कृपया निविदा दस्तावेज देखें।
- मैनुअल निविदायें स्वीकृत नहीं की जायेंगी।
- निविदा दस्तावेज और बयाना की लागत केवल ❖ जनभावना टाइम्स स्वीकार्य होगी।

सं: 128-W/280/e Tender Notice/NIT-04, 07 & 09-26-27-W-II दिनांक: 28.04.2026

1423/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

संपादकीय

ट्रंप के पास बचे तीन रास्ते

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान युद्ध को लेकर 1 मई की बड़ी चुनौती आने वाली है। दरअसल अमेरिका में युद्ध या सेना की तैनाती को लेकर विशेष नियम है। अमेरिकी वॉर पावर्स एक्ट के तहत बिना कांग्रेस की मंजूरी के वो साठ दिन से ज्यादा सेना को दूसरे देश में तैनात नहीं रख सकते। ऐसे में ट्रंप के सामने अमेरिकी संसद की मंजूरी के बिना सैन्य कार्रवाई जारी रखना मुश्किल होगा। फिलहाल उनके सामने केवल तीन विकल्प बचे हुए है। जानकारों का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए चुनौतीपूर्ण समय करीब आ रहा है। एक मई वह खास तारीख है जिस दिन ट्रंप को ईरान में अमेरिकी सैन्य अभियानों को लेकर अपना अंतिम फैसला लेना है। पूरी दुनिया की नजरें उनके अगले कदम पर टिकी हुई हैं। देखना है कि क्या वो कोई शांति समझौता करने का मन बनाएंगे। इससे अलग क्या वह देश के कड़े नियमों को नजरअंदाज करते हुए वैश्विक युद्ध की तरफ ले जाएंगे। हालांकि यह निर्णय काफी खतरनाक साबित हो सकता है। ट्रंप के सामने कूटनीतिक तौर पर शांति समझौता करना पहला विकल्प है। उनके सामने पहला और सुरक्षित रास्ता यह है कि वे ईरान के साथ बातचीत करके किसी शांतिपूर्ण समझौते पर पहुंच जाएं। उनके इस कदम से खाड़ी देशों में चल रहा तनाव कम होगा। विवादित होर्मुज क्षेत्र से तेल की आवाजाही फिर से सामान्य रूप से शुरू हो सकेगी। उनके सामने दूसरा विकल्प संसद में अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी है। एक मई को इस प्रस्ताव पर मंजूरी जरूरी है। हालांकि, विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के कड़े विरोध और मौजूदा राजनीतिक माहौल के चलते यह कानूनी विकल्प उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। उनके इस कदम को उनके दल के ही सांसद विरोध कर रहे है। प्रस्ताव की मंजूरी के लिए इसके लिए संसद में लंबी बहस का सामना करना पड़ेगा। अंतिम विकल्प उनके सामने एक मई की डेडलाइन को नजरअंदाज करना होगा। इसकी वजह यह है कि अगर हम अमेरिका के पुराने इतिहास पर नजर डालें तो कई राष्ट्रपतियों ने इस तरह के कड़े कानून को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। ट्रंप भी ऐसा ही कड़ा कदम उठाने का जोखिम ले सकते है। इसके तहत वह बिना इजाजत युद्ध जारी रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें भविष्य में बड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना पड़ सकता है। इसके अलावा देश में राजनीतिक रूप से छिछालेदर की भी उम्मीद है। तीनों विकल्पों के अलावा कूटनीतिक समाधान निकलने का इंतजार पूरी दुनिया को भी है। अधिकांश यूरोपीय देश चाहते है कि इस मसले का जल्द कोई कूटनीतिक समाधान निकाला जाए, ताकि वैश्विक मंदी से बचा जा सके। खाड़ी के देश इस पूरे घटनाक्रम को लेका काफी चिंतित है। उनका मानना है कि ततनाव से ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ेगा। एक मई को पुरी दुनिया की नजर अमेरिकी कांग्रेस में होने वाली अहम बैठक पर होगी। इसी बड़ी बैठक में वोटिंग से यह तय होगा कि ट्रंप प्रशासन को आगे के युद्ध के लिए अतिरिक्त बजट और सैन्य मंजूरी दी जाय या नहीं।

अब कमजोर मानसून व अल नीनो का जोखिम

हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2026 में कमजोर मानसून से भारत में कृषि की पैदावार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। इससे महंगाई बढ़नेऔर विकास दर में कमी की चुनौती होगी। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों 13 अप्रैल को भारतीय मौसम विभाग ने अल नीनो के कारण 2026 में सामान्य से कम मॉनसून का अनुमान लगाया है। यह पूर्वानुमान पिछले 26 वर्षों में मानसून का सबसे कम शुरुआती अनुमान है। इससे देश में कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने बारिश के दीर्घकालिक औसत (एलपीए) के 92 प्रतिशत रहने की संभावना बताई है। यह पूर्वानुमान 5 फीसदी अधिक या कम की मॉडल त्रुटि के साथ जारी किया गया है। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट की रिपोर्ट में भी इसी तरह का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में 75 प्रतिशत वर्षा पर आधारित मॉनसून सीजन (जून से सितंबर) में 5 प्रतिशत कम या ज्यादा के साथ 94 प्रतिशत वर्षा हो सकती है। यद्यपि पिछले आंकड़े बताते हैं कि सामान्य से कम मॉनसून वाले वर्षों में जब बारिश का समय, वितरण और फैलाव लगभग समान रहा, तब खरीफ के उत्पादन में अधिक कमी नहीं हुई, किन्तु गैर-सिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली दलहन और तिलहन जैसी फसलों के लिए जोखिम हो सकती हैं।

-डा. जयंतीलाल भंडारी-

चूंकि देश में अभी भी अनाज, दाल तथा तिलहन के उत्पादन का स्तर मौसम पर ही निर्भर होता है, ऐसे में क्षेत्रवार और फसलवार आधार का व्यापक अध्ययन करते हुए सिंचाई व्यवस्था की नई नीति तैयार करना लाभप्रद होगी। अनाज बर्बाद होने से बचाने के लिए देश में वर्ष 2028 तक सहकारी क्षेत्र में 700 लाख टन अनाज भंडारण की नई क्षमता विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जाना होगा।

हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2026 में कमजोर मानसून से भारत में कृषि की पैदावार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। इससे महंगाई बढने और विकास दर में कमी की चुनौती होगी। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों 13 अप्रैल को भारतीय मौसम विभाग ने अल नीनो के कारण 2026 में सामान्य से कम मॉनसून का अनुमान लगाया है। यह पूर्वानुमान पिछले 26 वर्षों में मानसून का सबसे कम शुरुआती अनुमान है। इससे देश में कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने बारिश के दीर्घकालिक औसत (एलपीए) के 92 प्रतिशत रहने की संभावना बताई है। यह पूर्वानुमान 5 फीसदी अधिक या कम की मॉडल त्रुटि के साथ जारी किया गया है। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट की रिपोर्ट में भी इसी तरह का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में 75 प्रतिशत वर्षा पर आधारित मॉनसून सीजन (जून से सितंबर) में 5 प्रतिशत कम या ज्यादा के साथ 94 प्रतिशत वर्षा हो सकती है। यद्यपि पिछले आंकड़े बताते हैं कि सामान्य से कम मॉनसून वाले वर्षों में जब बारिश का समय, वितरण और फैलाव लगभग समान रहा, तब खरीफ के उत्पादन में अधिक कमी नहीं हुई, किन्तु गैर-सिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली दलहन और तिलहन जैसी फसलों के लिए जोखिम हो सकती हैं। साथ ही दलहन और तिलहन का कम उत्पादन खाद्य महंगाई पर असर डाल सकता है। एक ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया संघर्ष से महंगे उर्वरक, महंगे तेल और आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से खेती की लागत बढ़ी है, तब कमजोर मानसून से न केवल किसानों और कृषि पर, वरना आम आदमी और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर हो सकता है।

साथ ही पेयजल समस्या की चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। ऐसे में किसानों व कृषि क्षेत्र के समक्ष दिखाई दे रही आसन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुआयामी रणनीति जरूरी है। गौरतलब है कि नीति आयोग के मुताबिक देश के कुल फसल रकबे का केवल 55 फीसदी सिंचित है और 45 प्रतिशत खेती मॉनसून पर निर्भर है। कम्पोजिट वॉटर मैनेजमेंट इंडेक्स (सीडब्ल्यूएमआई) के अनुसार लगभग 74 प्रतिशत गेहूं और 65 प्रतिशत चावल की खेती वाले क्षेत्र पहले से ही भारी जल संकट का सामना कर रहे हैं। व्यावसायिक फसलों और औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ते रुझान से भारत में मॉनसून की वर्षा पर निर्भरता बढ़ी हुई है। अब अल नीनो के खतरे और कमजोर मॉनसून की आशंका से जलाशय के सूखने और खेती के लिए पानी की कमी की चिंता बढ़ गई है। यह महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) देश में कुल 183.565 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) क्षमता वाले 166 प्रमुख जलाशयों के भंडारण पर नजर रखता है। सीडब्ल्यूसी का कहना है कि इस समय इन जलाशयों में कुल क्षमता का 44.71 प्रतिशत है। हाल के महीनों में इसमें तेजी से कमी आई है। प्राकृतिक पुनर्भरण प्रणाली कमजोर होने से भी हालात बिगड़ रहे हैं। वस्तुतः जलाशयों में पर्याप्त पानी 2025 के मॉनसून सीजन में अच्छी बारिश के कारण है, लेकिन अब इस साल कमजोर मॉनसून की आशंका से पानी का संग्रहित स्टॉक जल्दी खत्म हो सकता है। वास्तव में देश के किसानों और कृषि क्षेत्र की चिंताएं बढ़ाने वाला यह परिदृश्य देश के वर्तमान सुकूनदायक कृषि क्षेत्र के समक्ष एक चुनौती बनकर दिखाई दे रहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 2024-25 में भारत में 35.70 करोड़ टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और इस वर्ष 2025-26 में इससे भी अधिक खाद्यान्न उत्पादन की संभावना है। 2026 में गेहूं की खेती का रकबा भी पिछले वर्ष के 328.04 लाख हेक्टेयर की तुलना में बढ़कर लगभग 334.17 लाख हेक्टेयर हो गया है और एक और अच्छी फसल की संभावना का संकेत देता है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास केंद्रीय पूल में एक अप्रैल 2026 को लगभग गेहूं और चावल का 600 लाख टन से अधिक का उपलब्ध स्टॉक खाद्य सुरक्षा के मामले में भारत की मजबूती है। इस समय देश के 80 करोड़ से अधिक कमजोर वर्ग के लोगों को निशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रकाशित निर्यात आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 55 अरब डॉलर मूल्य का कृषि निर्यात किया है और भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कृषि निर्यात के लिए देश के कृषि निर्यात परिदृश्य पर यह उभकर दिखाई दे रहा है कि वर्ष 2014 से 2025 के बीच प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात चार गुना, फलों और दालों का निर्यात तीन गुना, खाद्यान्न का निर्यात दो गुना और चावल के निर्यात में करीब 62 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इतना ही नहीं पिछले करीब चार साल तक निर्यात पर नियंत्रण रखने के बाद भारत ने एक बार फिर अप्रैल 2026 से गेहूं के वैश्विक बाजार में वापसी का बड़ा संकेत दिया है। भारत सरकार ने घरेलू बाजारों को स्थिर करने और उत्पादकों को लाभकारी प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए एक निर्णायक और किसान-केंद्रित कदम उठाते हुए 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं और अतिरिक्त 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादों के निर्यात को मंजूरी दे दी है। मिस्र, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार और अफ्रीका के कई देश भारतीय गेहूं में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। ऐसे में इस वर्ष सामान्य से कम मानसून और खेती की बढ़ती लागत के मद्देनजर कई बातों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। यद्यपि अभी निर्धारित गेहूं के निर्यात आदेशों की पूर्ति अवश्य की जाए, लेकिन आगामी निर्यात आदेशों की पूर्ति के लिए सजगता रखी जाए। देश ने देखा है कि वर्ष 2021-22 में 70 लाख टन से अधिक गेहूं का निर्यात किया था, लेकिन वर्ष 2024 में गेहूं का आयात करना पड़ा। इस बात पर ध्यान देना होगा कि कम बारिश से जलाशयों में पानी का स्तर गिरने से सिंचाई और पीने के पानी की उपलब्धता प्रभावित होगी, ऐसे में अभी से जल संरक्षण के प्रयास शुरू होने चाहिए।

कृषि उत्पादन घटने की आशंका से खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। इस समय जो खुदरा महंगाई दर 3.40 प्रतिशत है, उसके बढने की आशंका होगी। अतएव मूल्यों की रोकथाम की रणनीति के साथ आगे बढना होगा। अब कृषि में प्रौद्योगिकी संस्कृति को बढ़ावा देने और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के विकास पर जोर दिया जाना होगा। व्यापक भंडारण अभियान और कृषि-वित्तीय प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं में नवाचार को बढ़ाने के प्रयास करने होंगे। चूंकि देश के विभिन्न हिस्सों में विविध जलवायु है और कृषि अनुकूल जलवायु क्षेत्रों के मामले में वह समृद्ध है, अतएव ऐसे में भारत को फसल विविधीकरण और खेती में आधुनिक तकनीक के एकीकरण के साथ आगे बढना होगा। चूंकि देश में अभी भी अनाज, दाल तथा तिलहन के उत्पादन का स्तर मौसम पर ही निर्भर होता है, ऐसे में क्षेत्रवार और फसलवार आधार का व्यापक अध्ययन करते हुए सिंचाई व्यवस्था की नई नीति तैयार करना लाभप्रद होगी। अनाज बर्बाद होने से बचाने के लिए देश में वर्ष 2028 तक सहकारी क्षेत्र में 700 लाख टन अनाज भंडारण की नई क्षमता विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जाना होगा। उम्मीद करें कि ऐसे प्रयासों से इस वर्ष 2026 में किसानों और कृषि क्षेत्र को मुश्किलों से बचाते हुए आम आदमी व अर्थव्यवस्था की चिंताएं भी कम की जा सकेंगी।

राघव चड्ढा ने खोद दिया आम आदमी पार्टी का गड्ढा

-मनोज कुमार अग्रवाल-

भारतीय राजनीति में दल बदल और आंतरिक बगावत कोई नई बात नहीं है लेकिन जब किसी उभरती हुई पार्टी के भीतर इस तरह का बड़ा घटनाक्रम सामने आता है तो उसके दूरगामी असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

हाल ही मेंराघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने अथवा दल-बदल/विलय के दावे से भारतीय राजनीति में कई गंभीर समस्याएं और विवाद उत्पन्न हो गए हैं। यह सबसे बड़ा कानूनी मुद्दा है कि क्या चड्ढा के साथ अन्य सांसदों का विलय संवैधानिक है। यह दलबदल विरोधी कानून की प्रासंगिकता और उसके दो-तिहाई वाले प्रावधान पर बहस छेड़ता है कि क्या सांसदों का एक बड़ा समूह रातों-रात पार्टी बदल सकता है। इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आरोप है कि उसके 10 में से 7 सांसद पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जो पार्टी के लिए एक अस्तित्व का संकट है। पार्टी के पूर्व सहयोगियों और समर्थकों की ओर से इसे वैचारिक विश्वासघात के रूप में देखा जा रहा है। आप ने आरोप लगाया है कि यह ऑपरेशन कमल के तहत भाजपा द्वारा उसके सांसद नेताओं को तोड़ने की कोशिश है। राघव चड्ढा को हाल ही में राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर पद से हटाया गया था, जिसके बाद यह बगावत हुई। यह पार्टी के भीतर चल रहे आंतरिक मतभेदों और नेतृत्व की पकड़ को उजागर करता है।इस प्रकार के बड़े पैमाने पर दल-बदल से अस्थिरता का युग वापस आने की चिंता बढ़ गई है, जिससे लोकतंत्र के भविष्य पर सवाल उठते हैं।

आपको पता है कि राघव चड्ढा और उनके साथ कई राज्यसभा सांसदों का आम आदमी पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत देता है। यह केवल व्यक्तियों का दल बदल नहीं बल्कि एक संगठन की आंतरिक स्थिति और उसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आम आदमी पार्टी ने अपने गठन के समय खुद को एक वैकल्पिक राजनीति के रूप में प्रस्तुत किया था। ईमानदारी पारदर्शिता और जनहित के मुद्दों को केंद्र में रखकर इस पार्टी ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की। दिल्ली में लगातार जीत और पंजाब में सरकार बनाना इस बात का प्रमाण था कि जनता ने इस पार्टी को स्वीकार किया है। लेकिन अब जिस तरह से पार्टी के भीतर असंतोष और टूट सामने आ रही है वह यह संकेत देता है कि अंदरूनी ढांचे में कहीं न कहीं कमजोरी मौजूद है। राघव चड्ढा का पार्टी से अलग होना अचानक नहीं हुआ। पिछले कुछ वर्षों से उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच दूरी की खबरें सामने आती रही थीं। महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थिति सोशल मीडिया पर अलग पहचान बनाने की कोशिश और संगठनात्मक गतिविधियों से दूरी यह सभी संकेत पहले से मौजूद थे। जब उन्हें राज्यसभा में उपनेता पद से हटाया गया तो यह स्पष्ट हो गया कि संबंध सामान्य नहीं रहे हैं। इसके बाद उनका इस्तीफा और फिर भाजपा में शामिल होना एक तय दिशा की ओर बढ़ता कदम प्रतीत होता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है दो तिहाई सांसदों का गणित। भारतीय संविधान के तहत दल बदल कानून यह कहता है कि यदि किसी पार्टी के दो तिहाई सांसद एक साथ दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो उनकी सदस्यता सुरक्षित रहती है। यही कारण है कि राघव चड्ढा ने अपने साथ पर्याप्त संख्या में सांसदों को जोड़ने का प्रयास किया। यह केवल राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम भी था जिससे उनकी संसदीय स्थिति बनी रहे।

यहां सवाल उठता है कि क्या यह केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का मामला है या फिर पार्टी की कार्यप्रणाली में वास्तविक समस्याएं हैं। जब एक दो नहीं बल्कि कई सांसद एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो यह संकेत देता है कि असंतोष व्यापक है। स्वाति मालीवाल जैसे नेताओं का पहले से असहज होना और अन्य नेताओं का अचानक अलग होना यह दर्शाता है कि संवाद और विश्वास की कमी रही है। अब तुलना शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से की जा रही है। इन दोनों दलों में भी इसी तरह की टूट देखने को मिली थी जहां दो तिहाई विधायकों के अलग होने से पार्टी का नियंत्रण बदल गया। हालांकि वर्तमान स्थिति में आम आदमी पार्टी के मामले में यह टूट राज्यसभा तक सीमित है इसलिए सरकार पर तत्काल कोई खतरा नहीं है। लेकिन यदि यही स्थिति पंजाब विधानसभा तक पहुंचती है तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं।

पंजाब इस समय आम आदमी पार्टी का सबसे मजबूत आधार है। यदि वहां भी इसी तरह का असंतोष पैदा होता है और बड़ी संख्या में विधायक अलग होते हैं तो पार्टी की पहचान और अस्तित्व दोनों पर खतरा आ सकता है। इसलिए यह घटनाक्रम केवल एक संसदीय बदलाव नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाओं का संकेत भी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह घटनाक्रम कई मायनों में लाभकारी है। पहला राज्यसभा में उसकी संख्या बढ़ेगी। राघव चड्ढा के साथ आप के 10 में से 7 राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल हुए हैं, जिससे उच्च सदन में भाजपा की संख्या बढ़कर 113 हो गई है और उसे अहम विधेयकों को पास कराने में आसानी होगी।

यह दलबदल आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब और दिल्ली में एक बड़ा झटका है, जहाँ चड्ढा एक प्रमुख युवा चेहरा थे। चड्ढा का रोल सिर्फ टीवी और संसद तक सीमित नहीं था. पंजाब में संगठन खड़ा करने और दिल्ली-पंजाब के बीच समन्वय बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रही है. उनके जाने से यह कनेक्शन कमजोर पड़ सकता है. खासतौर पर तब, जब आम आदमी पार्टी खुद को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है. इससे भाजपा को पंजाब चजहाँ अगले साल चुनाव होने हैं में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिल सकती है ।राघव चड्ढा की छवि एक पढ़े-लिखे, आक्रामक और सलीकेदार प्रवक्ता की है, जो भाजपा के मीडिया और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट को और अधिक धारदार बना सकती है।

चड्ढा ने पार्टी द्वारा अपने मूल सिद्धांतों से भटकने का आरोप लगाया है, जिससे भाजपा को आप के खिलाफ अपने 'भ्रष्टाचार' के नैरेटिव को और मजबूत करने का मौका मिल गया है। चड्ढा के साथ आने से उन विधायकों और कार्यकर्ताओं के भी भाजपा में आने की संभावना बढ़ गई है, जो पंजाब और दिल्ली में उनके प्रभाव में थे। कुल मिलाकर, यह कदम न केवल भाजपा के संख्या बल को बढ़ाता है, बल्कि आम आदमी पार्टी की साख पर भी सवाल उठाता है। राजनीति में हर खबर अपने साथ एक मैसेज भी लेकर आती है. चड्ढा जैसे नेता का बीजेपी में जाने का मतलब है कि बीजेपी विपक्ष के सॉफ्ट, अर्बन और प्रोफेशनल स्पेस में एंट्री चाहती है और आप के भीतर स्थिरता को लेकर सवाल उठने लगे हैं ।राघव चड्ढा की एंट्री से बीजेपी को एक ऐसा चेहरा मिलेगा जो उसके विस्तार को नया आयाम दे सकता है और आप को पहली बार अपने ही बनाए नैरेटिव की असली परीक्षा देनी पड़ेगी। सवाल अब यही है कि क्या यह सिर्फ एक नाम की कहानी है, या आने वाले समय में सियासत का नया ट्रेंड? को पहली बार अपने ही बनाए नैरेटिव की असली परीक्षा देनी पड़ेगी. सवाल अब यही है कि क्या यह सिर्फ एक नाम की कहानी है, या आने वाले समय में सियासत का नया चेहरा दिखाएगा?

ऐसे करें मृत्युकारक ग्रहों की पहचान

महामारकेश क्या है, कुण्डली में मृत्युकारक ग्रहों की कैसे करें पहचान आठवाँ व बारहवाँ भाव मृत्यु और शारीरिक क्षय को प्रकट करता है। लग्न व लग्नेश आयु को दर्शाता है, इसकी नेष्ट स्थिति भी आयु के लिए घातक होती है। किसी भी व्यक्ति की कुण्डली के बारह भावों में बारह राशियों सहित नौ ग्रह विद्यमान होते हैं। सात मुख्य ग्रहों के साथ ही दो छाया ग्रहों, राहु व केतु की व्यक्ति के जीवन में महती भूमिका होती है। अलग-अलग राशि तथा लग्न के जातकों के लिए कारक व मारक ग्रह भी अलग-अलग अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार होते हैं। यहां पर हम केवल किसी जातक की जन्म कुण्डली में किस समय कौन सा ग्रह मारक बनेगा, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि मारक शब्द का ज्योतिषीय अर्थ क्या है? ज्योतिष शास्त्र में मारक व मारकेश की खूब चर्चा होती है। सामान्यजन के लिए ये एक भारी चिंता का विषय भी बन जाता है कि कहीं उनकी कुण्डली में कोई खास ग्रह मारक तो नहीं? जबकि हकीकत जाने बिना एक संशय व डर से पीड़ित रहना कहां की बुद्धिमानी है। तो आइए जानते हैं कुछ बेहद जरूरी तथ्य ताकि आपका भ्रम भी दूर हो सके साथ ही आप कथित ज्योतिष विशेषज्ञों के जाल में फंसने से भी बच सकें। वस्तुतः प्रत्येक जातक की कुण्डली में स्वयं उसके लिए द्वितीयेश तथा सप्तमेश हमेशा मारक का कार्य करते हैं। हालांकि द्वितीयेश तथा सप्तमेश स्वयं में धनेश तथा विवाह के स्वामी भी होते हैं। किंतु यही ग्रह जब शुभ केंद्रेश होकर त्रिशडायेश स्थानों में अथवा छठे, आठवें या बारहवें स्थान पर बैठे हों तो महान पापी होकर मृत्यु कारक बन जाते हैं। वहीं चन्द्रमा, बुध, अथवा सूर्य में सप्तमेश या द्वितीयेश होने के बावजूद भी मारकत्व की क्षमता कम होती है ।ऐसे में आम जातक के मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि ये क्या बात हुई कि नैसर्गिक शुभ ग्रहों में मारकत्व की अधिक क्षमता जबकि नैसर्गिक पापी व क्रूर ग्रहों में मारकत्व की कम क्षमता होती है? वस्तुतः यहां पाराशरी का सामान्य सिद्धांत कार्य करता है, जिसकी पुष्टि वृहत पाराशर होरा शास्त्र सहित स्वयं कालामृतकार भी करते हैं।

आज का इतिहास

1706 - सम्राट जोज़ेफ़ आई को कोलोन और बवेरिया का राजा बनाया गया।

1770 - ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में उतरने वाले पहले यूरोपीय जहाज एचएमएस एंडेवर के चालक दल, वर्तमान सिडनी के पास बॉटनी खाड़ी के तट पर पहुंच गए।

1781 - अमेरिकी युद्ध स्वतंत्रता के दौरान फ्रैंच बेड़े टोबैगो में रह गया।

1784 - बी फ्लैट, K454 (वियना) में मोजार्ट के सोनाटा का प्रीमियर हुआ।

1805 - रुचर जेन स्चिमेल्पेनिनक को नेपोलियन द्वारा बैटवियन गणराज्य के ग्रांड पेंशनरी के रूप में नियुक्त किया गया।

1817 - रश-बैगोट संधि पर हस्ताक्षर किए गए।

1862 - डेविड फर्रागुत के तहत अमेरिकी नागरिक युद्ध-संघ बलों ने मिसिसिपी नदी में पहुंच हासिल करने के लिए न्यू ऑरलियन्स पर कब्जा कर लिया।

1882 - दुनिया का पहला ट्रॉलीबस आपरेशन बर्लिन में शुरू किया गया।

1903 - कनाडा के उत्तर-पश्चिम प्रदेश में हुए भूस्खलन से 70 लोगों की मौत।

1946 - सुदूर पूर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण ने हिदेकी तोजो और 27 अन्य जापानी नेताओं को युद्ध अपराधों के लिए प्रेरित किया।

1965 - पाकिस्तान के अंतरिक्ष और ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान आयोग ने अपने सातवें रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया।

1968 - विवादास्पद म्यूजिकल हेयर, 1960 के हिप्पीकाउंटर-संस्कृति और यौन क्रांति का एक उत्पाद, ब्रॉडवे पर बिल्टमोर थिएटर में खोला गया, जिसमें इसके गाने थेन्ती-वियतनाम युद्ध आंदोलन के गान बन गए।

1970 - वियतनाम युद्ध-दक्षिण वियतनामी सेना ने कम्युनिस्ट जंगल के ठिकानों पर हमला करने के लिए कंबोडिया में घुसपैठ शुरू की।

1991 - बंगलादेश के चटगांव मे आए एक चक्रवाती तूफान में एक लाख 38 हजार लोग मारे गए और दस लाख लोग बेघर हो गए।

ट्रंप को अमेरिका के कई राज्यों में मिल रही चुनौती

-भानु धमीजा-

राज्य और स्थानीय सरकारें भी ट्रंप की कार्यवाही रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। 20 से अधिक राज्यों ने ट्रंप के संघीय फंडिंग को फ्रीज करने के प्रयास को सफलतापूर्वक चुनौती दी है। शिक्षा के क्षेत्र में, अदालतों ने डीईआई यानी डायवर्सिटी, इक्विटी एंड इनक्लूजन (विविधता, समानता और समावेश) पहलों को सीमित करने के लिए कई प्रयासों को खारिज कर दिया है, यह मानते हुए कि ऐसे उपाय संघीय अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। साथ ही, राजनीतिक समर्थन में कमजोरी के संकेत यह बताते हैं कि ट्रंप को आगे और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। पिछले 14 महीनों में, डेमोक्रेट्स ने राज्य विधानसभाओं में 28 रिपब्लिकन सीटों को पलट दिया है, जो यह संकेत देता है कि चुनावी गतिशीलता बदल रही है, जो प्रशासन के एजेंडे को सीमित कर सकती है।

यह विडंबना है कि राजा और राष्ट्रपति के बीच के अंतर को स्पष्ट करने का कार्य अलेक्जेंडर हैमिल्टन को सौंपा गया। दरअसल, हैमिल्टन ने अमरीका की संविधान सभा की शुरुआत में ब्रिटिश राजशाही की तर्ज पर एक राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव दिया था, जिसमें आजीवन कार्यकाल और व्यापक वीटो शक्तियां शामिल थीं। जब 1787 की संविधान सभा में उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया गया, तो वह नाराज होकर सभा से बाहर चले गए, और कई हफ्तों बाद वापस लौटे। लेकिन अंततः वह उस अमरीकी राष्ट्रपति पद के सबसे मजबूत समर्थकों में से एक बन गए जैसा कि सभा में डिजाइन किया गया था, और इसके समर्थन में अधिकांश फेडरलिस्ट पेपर्स लिखे। फेडरलिस्ट नंबर 69 में उन्होंने अमरीकी राष्ट्रपति और राजा के बीच तुलना को गलत ठहराया, यह बताते हुए कि राष्ट्रपति को चुना जाएगा, वह नियमित चुनावों के अधीन होगा, और उसको महाभियोग का सामना करना पड़ सकता है।

अमरीका के इतिहास में, राष्ट्रपति पर अक्सर यह आरोप लगाया गया है कि वे राजाओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं या अपनी संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन को उनके औपचारिक शैली और समारंभिक उपस्थिति के लिए आलोचना की गई थी। जेफरसनियन रिपब्लिकन ने उन्हें 'लोकप्रिय प्रशंसा में, राजा की तरह डूबे हुए' कहा। एंड्रयू जैक्सन को उनके वीटो के आक्रामक उपयोग के कारण 'किंग एंड्रयू द फर्स्ट' उपनाम मिला। अब्राहम लिंकन को civil war के दौरान हैबियस कॉर्पस निलंबित करने के लिए एक तानाशाह कहा गया। थियोडोर रुजवेल्ट को उनकी कार्यकारी शक्तियों के विस्तार के कारण 'थियोडोर रेक्स' उपनाम मिला, और उनके कजिन फ्रैंकलिन रुजवेल्ट को सुप्रीम कोर्ट के विस्तार का प्रस्ताव देने पर 'राजसी' महत्वाकांक्षाओं का आरोप लगा। रिचर्ड निक्सन के राष्ट्रपति पद ने 'इम्पीरियल प्रेसीडेंसी' शब्द को जन्म दिया, और बराक ओबामा को उनके कार्यकारी आदेशों के व्यापक उपयोग के कारण 'धूर्त राजा' कहा गया। पिछले माह, आठ मिलियन से अधिक अमरीकियों ने 'नो किंग्स रैलीज' में भाग लिया, जो राष्ट्रपति ट्रंप के ऐसे कृत्यों का विरोध कर रहे थे जिन्हें आलोचकों ने तानाशाही पूर्ण बताया। सर्वेक्षणों से भी समान चिंताएं सामने आई हैं। पिछले महीने एक रिपोर्ट, जो लगभग 600 राजनीतिक वैज्ञानिकों के उत्तरों पर आधारित थी, ने संयुक्त राज्य अमरीका को एक उदार लोकतंत्र और एक तानाशाही के बीच स्थित बताया। इसी तरह, स्वीडन के वी. डेम इंस्टीट्यूट ने अमरीकी लोकतंत्र की वैश्विक रैंकिंग में एक तेज गिरावट दर्ज की, जो 179 देशों में 20वें स्थान से गिरकर 51वें स्थान पर पहुंच गई। लेकिन ग्राउंड पर जो घटनाएं हो रही हैं, वे यह संकेत देती हैं कि राष्ट्रपति की अनियंत्रित शक्तियों के बारे में डर कुछ हद तक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है।

हाल की कानूनी विफलताएं और राज्य और स्थानीय सरकारों से प्रतिरोध यह दर्शाते हैं कि ट्रंप प्रशासन के पास पूरी तरह से निरंकुश अधिकार नहीं हैं। चुनावी रुझान भी संभावित प्रतिबंधों की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी की हाल की हार से यह संभावना बन रही है कि कांग्रेस में एक और जांच होगी, या फिर ट्रंप के खिलाफ एक और महाभियोग प्रक्रिया चल सकती है, जो कथित शक्ति के दुरुपयोग के कारण हो सकता है। कंजर्वेटिव दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट के बावजूद, ट्रम्प प्रशासन को महत्वपूर्ण न्यायिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। जनवरी 2025 के बाद से, इसे 350 से अधिक मुकदमों का सामना करना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप 25 से अधिक ट्रम्प के राष्ट्रीय आदेशों को रोका गया है, जिससे प्रमुख नीतियां लागू होने से पहले रुक गईं।

यह न्यायिक प्रतिरोध विशेष रूप से ट्रम्प के महत्वपूर्ण नीति क्षेत्रों में देखा गया है। संघीय अदालतों ने बार-बार जन्म आधारित नागरिकता, टैरिफ और अवैध प्रवासियों की हिरासत से जुड़ी प्रमुख कार्यकारी कार्रवाइयों को रोक दिया है। बोस्टन में एक संघीय न्यायाधीश ने प्रशासन के जन्म आधारित नागरिकता समाप्त करने के प्रयास को रोक दिया, यह कहते हुए कि यह अमरीकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। फरवरी में, कोर्ट ने प्रशासन की टैरिफ नीति को भी खारिज कर दिया। इस बीच, अवैध प्रवासियों की अनिवार्य हिरासत नीतियों को सैकड़ों मामलों में चुनौती दी गई है, जिनमें सरकार के खिलाफ कई निर्णय दिए गए हैं।

अदालतों के अलावा, ट्रम्प के संघीय प्रशासन के पुनर्गठन के प्रयासों को मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। यूएसएआईडी जैसी एजेंसियों को कम करने के प्रयास, जिनमें अधिकांश कार्यक्रमों को समाप्त करना शामिल था, कानूनी विवादों में उलझे हुए हैं। इसके अलावा, एक डिस्ट्रिक्ट जज ने हजारों बरखास्त सरकारी कर्मचारियों को पुनः बहाल करने का आदेश दिया, जो यह दर्शाता है कि कार्यकारी शाखा को कर्मचारियों के निर्णयों पर नियंत्रण में सीमाएं हैं। राज्य और स्थानीय सरकारें भी ट्रम्प की कार्यवाही रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। 20 से अधिक राज्यों ने ट्रंप के संघीय फंडिंग को फ्रीज करने के प्रयास को सफलतापूर्वक चुनौती दी है। शिक्षा के क्षेत्र में, अदालतों ने डीईआई यानी डायवर्सिटी, इक्विटी एंड इनक्लूजन (विविधता, समानता और समावेश) पहलों को सीमित करने के लिए कई प्रयासों को खारिज कर दिया है, यह मानते हुए कि ऐसे उपाय संघीय अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। साथ ही, राजनीतिक समर्थन में कमजोरी के संकेत यह बताते हैं कि ट्रंप को आगे और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा।

पिछले 14 महीनों में, डेमोक्रेट्स ने राज्य विधानसभाओं में 28 रिपब्लिकन सीटों को पलट दिया है, जो यह संकेत देता है कि चुनावी गतिशीलता बदल रही है, जो प्रशासन के एजेंडे को सीमित कर सकती है। जबकि कार्यकारी शाखा की अधिक शक्ति के बारे में चिंताएं वैध हैं, तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की शक्तियां निरंकुश नहीं हैं। अमरीकी लोकतंत्र के संस्थागत सुरक्षा तंत्र- अदालतें, राज्य सरकारें, और चुनाव- अभी भी महत्वपूर्ण सीमाएं लगा रहे हैं। भले ही ये तंत्र दबाव में हों, अमरीकी लोकतंत्र के संवैधानिक सुरक्षा उपाय मजबूत बने हुए हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक आदित्य वशिष्ठ द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस, बी-42 सेक्टर -7 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301 से मुद्रित व बी-142/2, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 से प्रकाशित।
संपादकीय एवं संपर्क कार्यालय ए-152 सेक्टर-63, नोएडा-201301 **संपादक - आदित्य वशिष्ठ** कानूनी सलाहकार-पवित्र मोहन शर्मा आर.एन.आई. DELHIN/2012/42452
इस अंक में प्रकाशित सभी समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी होंगे। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे। e-mail: Jbttimes2021@ gmail. Com

पीएम मोदी ने देश की आधी आबादी को वह सम्मान दिया, जो पूर्ववर्ती सरकारें नहीं दे सकीं: नितिन नवीन

'जनआक्रोश महिला सम्मेलन' में भाजपा अध्यक्ष नवीन ने किया काशी की महिमा का गुणगान

वाराणसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को बरेका में आयोजित 'जनआक्रोश महिला सम्मेलन' में केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का जमकर गुणगान किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले एक दशक से प्रधानमंत्री ने देश की आधी आबादी को वह सम्मान दिया है, जो पूर्ववर्ती सरकारें नहीं दे सकीं। प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपनी ही मां का सम्मान नहीं किया बल्कि देश की माताओं का भी सम्मान किया है।

प्रधानमंत्री मोदी की जमकर प्रशंसा करते हुए नवीन ने कहा कि वह उस मां को नमन करते हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जैसे पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए कार्य सराहना और गर्व के पात्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से आज करोड़ों महिलाओं को चुल्हें के धुएं से मुक्ति मिली है।

केंद्र व राज्य में महिलाओं के हित में उठाए गए कदमों का उल्लेख कर उन्हो कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चाहे हर घर शौचालय हो या उज्ज्वला योजना, इससे आपके आसुओं को पोंछने का काम किया। लेकिन विपक्ष ने आपका रास्ता रोकने का काम किया है। लेकिन हमें पता है कि जब-जब पीएम ने संकल्प लिया, उसे पूरा किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को घर का मालिकाना हक दिया गया, जिससे उनका सामाजिक सम्मान बढ़ा है। आज महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नए अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं के जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आया है, वह अभूतपूर्व है। आज महिलाएं एआई से लेकर ओलंपियाड और खेल का नेतृत्व कर रही हैं। बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी योजनाओं से महिलाएं और बेटियां सशक्त हो रही हैं। ट्रिपल तलाक पर लिए गए फैसले से मुस्लिम महिलाओं को सम्मान मिला है।

भाजपा अध्यक्ष ने काशी की महिमा का उल्लेख करते हुए कहा कि काशी केवल एक शहर या भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि एक जीवंत चेतना भी है। जिस प्रकार मां गंगा भारतीय संस्कृति को सिंचित करती हैं, उसी प्रकार देश की महिलाएं परिवार और समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जनसभा में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बिहटा में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र के उद्घाटन से 'मेक इन बिहार' को मिलेगी नई रफ्तार : सीएम

रफ्तार पकड़ता बिहारः पटना में टेक्नोलॉजी सेंटर का हुआ उद्घाटन

पटना। बिहार के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने की पहल के तहत मंगलवार को पटना के बिहटा में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संयुक्त रूप से केंद्र का शुभारंभ किया।

यह केंद्र राज्य में तकनीकी प्रशिक्षण, रोजगार सृजन और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि आज का दिन बिहार के औद्योगिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि बिहटा में स्थापित यह प्रौद्योगिकी केंद्र और इसके विस्तार केंद्र आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं और उद्यमियों को सशक्त बनाएंगे। इससे उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने इसे 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को जमीनी स्तर पर साकार करने की दिशा में एक ठोस पहल बताया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि यह टेक्नोलॉजी सेंटर 'मेक इन बिहार' के विजन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार तेजी से औद्योगिक प्रगति की ओर अग्रसर है और यह केंद्र उस परिवर्तन का सशक्त प्रतीक बनेगा।

राज्य सरकार का लक्ष्य युवाओं को बेहतर कौशल, आधुनिक संसाधन और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है, ताकि वे केवल रोजगार पाने वाले नहीं, बल्कि रोजगार सृजक भी बन सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र निवेश, नवाचार और उद्यमिता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बिहटा में स्थित यह प्रौद्योगिकी केंद्र अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है, जो इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही बिहार की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ग्रामोद्योग विकास योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के लाभार्थियों को विभिन्न सहायता प्रदान की गई।

पीएम विश्वकर्मा योजना और ग्रामोद्योग विकास योजना के लाभार्थियों को टूलकिट वितरित किए गए, जबकि पीएमईजीपी योजना के लाभार्थियों को चेक सौंपे गए। इसके अलावा एससी/एसटी हब योजना के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र भी वितरित किए गए। इन योजनाओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया।

एक दिन में 500 दीवारें रंगने का लक्ष्य: रंग दे गुलाबी अभियान 2 मई को

जयपुर। नगर निगम जयपुर शहर को और अधिक आकर्षक व जीवंत बनाने की दिशा में एक नई पहल करते हुए 2 मई 2026 को 'रंग दे गुलाबी' अभियान शुरू करेगा। इस अभियान के तहत देश में पहली बार एक ही दिन में 500 दीवारों को रंगने का लक्ष्य रखा गया है।

आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई यह पहल शहर की सुंदरता बढ़ाने के साथ जनभागीदारी का बड़ा उदाहरण बनेगी। नगर निगम सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में निगम नगर आयुक्त ओम कसेरा ने इसे जयपुर के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि 'सफाई सेवा मैराथन' के जरिए स्वच्छता का मजबूत आधार तैयार करने के बाद अब शहर को सौंदर्य की नई पहचान देने की दिशा में यह अगला प्रयास है। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि 'रंग दे गुलाबी' केवल गुलाबी रंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शहर की दीवारों पर पारंपरिक गुलाबी के साथ-साथ विविध आकर्षक और कलात्मक रंगों का उपयोग किया जाएगा। इससे अलग-अलग क्षेत्रों को नई पहचान मिलेगी और जयपुर की सांस्कृतिक विरासत आधुनिक रूप में नजर आएगी। अभियान में स्कूल, कॉलेज, एनजीओ, निजी संस्थाएं, कॉर्पोरेट समूह और आम नागरिक स्वेच्छा से भाग ले सकेंगे।

पेंटिंग सेवाएं देने के इच्छुक व्यक्ति एवं संस्थाएं 7470651609 और 7878252518 पर संपर्क कर सकते हैं। नगर निगम ने बताया कि चयनित 500 दीवारों की जानकारी पेंटिंग से पहले और बाद में मीडिया व आमजन के साथ साझा की जाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। नगर निगम ने जयपुर वासियों से अपील की है कि वे इस अभियान से जुड़कर शहर को स्वच्छ, सुंदर और रंगीन बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं।

सरसंघचालक डॉ. भागवत दो मई को मुंबई में 'कर्मयोगी एकल शिक्षक मेला' में करेंगे संवाद

सरसंघचालक डॉ. भागवत करेंगे शिक्षकों से संवाद, वनवासी शिक्षा विस्तार पर होगा गहन मंथन

मुंबई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत 02 मई को मुंबई में आयोजित "कर्मयोगी एकल शिक्षक मेला" में वनवासी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए कार्यरत शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य के आदिवासी विकास मंत्री प्रो. अशोक उइके भी उपस्थित रहेंगे।

नागपुर स्थित कै. लक्ष्मणराव मानकर स्मृति संस्था के संचालित एकल विद्यालय पहल को अब विदर्भ से बढ़ाकर पूरे महाराष्ट्र में विस्तार देने की योजना तैयार की गई है। इस कार्यक्रम में इसी विस्तार योजना की विस्तृत जानकारी भी साझा की जाएगी। करीब तीन दशक पहले शुरू हुई इस पहल ने विदर्भ के दूरस्थ वनवासी क्षेत्रों में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में गढ़चिरौली, मेलघाट सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 1300 विद्यालयों के माध्यम से 30 हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जबकि 1800 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। संस्था ने अब पूरे महाराष्ट्र में इस मॉडल को और विस्तारित करने का लक्ष्य रखा है। योजना के तहत 5 हजार विद्यालय, 6 हजार शिक्षक तथा 01 लाख वनवासी विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस पहल का संचालन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन और मुंबई के उद्योगपति अतुल शिरोडकर की अध्यक्षता में किया जा रहा है। संस्था का उद्देश्य वनवासी समुदाय को शिक्षा, कौशल विकास और मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम है, और संस्था इसी दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

कर्मयोगी पुरस्कार और सांस्कृतिक कार्यक्रम2 मई को शाम 6 बजे होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान नवनिर्वाचित राज्य सभा सदस्य मायाताई इवनाते को सम्मानित किया जाएगा और पंडित नीलाद्री कुमार का सितार वादन होगा। आयोजन के मौके पर, राज्य में सामाजिक क्षेत्र के अलग-अलग लोग एक साथ आकर जंगल में रहने वालों की शिक्षा के आंदोलन को नई दिशा देने पर मंथन करेंगे। संगठन ने हर तबके के नागरिकों से इस काम में सहयोग करने की अपील की है। यह कार्यक्रम वनवासी समुदाय की ज़िंदगी में बदलाव लाने के इस आंदोलन को तेज़ करने में एक अहम कदम होगा।

शेयर मार्केट में भारी मुनाफे का लालच देकर 1.45 करोड़ की ऑनलाइन ठगी

हरिद्वार। सिडकुल क्षेत्र में फार्मा कंपनी के एक कर्मचारी से ऑनलाइन शेयर मार्केट में बड़े मुनाफे का सपना दिखाकर 1.45 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मंगलवार को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हरिद्वार ग्रीन सोसाइटी के निवासी नीरज कुमार ने शिकायत में बताया कि जनवरी 2026 में फेसबुक पर निवेश संबंधी एक विज्ञापन देखने के बाद उन्होंने लिंक पर संपर्क किया तो उन्हें ग्रुप में जोड़कर शेयर मार्केट में निवेश का ऑफर दिया गया। आरोपितों ने स्वयं को प्रतिष्ठित निवेश सलाहकार बताया और भारी मुनाफे का भरोसा देकर नियो कोट प्रो ऐप डाउनलोड करवाया। शिकायत के अनुसार शुरुआत में एप पर निवेश राशि और लाभ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में विश्वास बढ़ने पर आरोपितों ने अलग-अलग बैंक खातों में बड़ी धनराशि ट्रांसफर कराई। कुल मिलाकर उन्होंने एक करोड़ 45 लख रुपए जमा करवाए। लेकिन जब राशि निकालने का प्रयास किया तो राशि ट्रांसफर नहीं हुई। इसके बाद आरोपित संपर्क से बाहर हो गए। खुद के साथ ठगी का एहसास होने पर उन्होंने साइबर सेल और पुलिस को शिकायत की। सिडकुल थाना प्रभारी अजय शाह ने बताया मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

गडकरी ने ओडिशा में 5,390 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा व गुणवत्ता पर जोर दिया

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ओडिशा में 5,390 किलोमीटर लंबाई के 124 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की व्यापक समीक्षा की।

मीडिया और सोशल मीडिया से प्राप्त फीडबैक के आधार पर यह समीक्षा की गई। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा के साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और परियोजना से जुड़े ठेकेदारों के अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान गडकरी ने महत्वपूर्ण खंडों पर लक्षित हस्तक्षेप, परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन और गुणवत्ता मानकों के सख्त पालन पर जोर दिया, ताकि परिसंपत्तियों का दीर्घकालिक प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को मानसून से पहले अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए जल निकासी प्रबंधन, ढलान सुरक्षा और प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र पर विशेष ध्यान देने को कहा, जिससे सड़क सुरक्षा बनी रहे और यातायात का सुचारु संचालन सुनिश्चित हो सके।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिश्केक में चीन, रूस के समकक्षों से मुलाकात की

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को बिश्केक में अपने चीनी समकक्ष एडमिरल डोंग जून से मुलाकात की और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के संबंध में चर्चा की। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के इतर यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब भारत और चीन अपने तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने की दिशा में प्रयासरत हैं।

सिंह ने सोशल मीडिया पर कहा कि बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून से बातचीत कर खुशी हुई। इस बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि सिंह और डोंग के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई। पता चला है कि सिंह और डोंग ने एलएसी पर समग्र स्थिति के संबंध में चर्चा की, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व के साथ-साथ क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर भी जोर दिया गया। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि वार्ता में पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा हुई या नहीं। यह बैठक भारत और चीन के संबंधों को सुधारने के प्रयासों के बीच हुई है। पिछले कुछ महीनों में, दोनों पक्षों ने अपने संबंधों को फिर से सुधारने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा हो गया था।

राजनयिक और सैन्य स्तर पर कई दौर की वार्ताओं के बाद, दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ गतिरोध वाले कई बिंदुओं से अपने-अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। रक्षा मंत्री ने रूस के अपने समकक्ष आंद्रेई बेलोसोव से भी मुलाकात की। सिंह ने कहा कि बिश्केक में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव के साथ बातचीत अच्छी रही। पता चला है कि सिंह और बेलोसोव ने रूस द्वारा भारत को एस-400 वायु रक्षा मिसाइलों की आपूर्ति सहित विभिन्न रक्षा खरीद परियोजनाओं पर चर्चा की।

अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस के साथ पांच अरब अमेरिकी डॉलर का समझौता किया था, जिसके तहत पांच मिसाइल प्रणाली इकाइयों की खरीद की जानी थी, और इनमें से तीन इकाइयां पहले ही भारत को सौंप दी गई हैं। चौथी इकाई के अगले कुछ दिनों में मिलने की उम्मीद है, जबकि पांचवीं इकाई नवंबर में भेजे जाने की संभावना है। पिछले महीने, भारत ने रूस से एस-400 मिसाइल प्रणाली की नयी खेप के तहत पांच और प्रणालियों की खरीद को मंजूरी दे दी, जिससे इनकी कुल संख्या 10 हो जाएगी।

केंद्र ने श्रमिकों की लू से सुरक्षा के लिए राष्ट्रव्यापी परामर्श जारी किया

नई दिल्ली। भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी करते हुए कर्मियों और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए तत्काल निवारक तथा राहत उपाय अपनाने का आग्रह किया है।

मंत्रालय ने मुख्य सचिवों और प्रशासकों को भेजे पत्र में कहा है कि विशेष रूप से बाहरी और श्रम-प्रधान क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समन्वित और बहु-आयामी रणनीति अपनाई जाए। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि वे नियोक्ताओं, ठेकेदारों, उद्योगों और निर्माण कंपनियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें। इनमें काम के घंटों का पुनर्निर्धारण, पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना तथा कार्यस्थलों और विश्राम स्थलों को ठंडा

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
Ministry of Labour & Employment
भारत सरकार (Government of India)

रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करना शामिल है। परामर्श में यह भी कहा गया है कि निर्माण स्थलों सहित विभिन्न कार्यस्थलों पर आपातकालीन आइस पैक और गर्मी से बचाव की सामग्री उपलब्ध कराई जाए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर श्रमिकों के स्वास्थ्य की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए। कारखानों और खदानों के प्रबंधन को अत्यधिक गर्मी के दौरान कार्य की गति धीमी करने, आवश्यक होने पर दो श्रमिकों की टीम तैनात करने, विश्राम की व्यवस्था करने और कार्यस्थलों को हवादार तथा ठंडा रखने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने निर्माण श्रमिकों, ईंट भट्ठों में काम करने वाले मजदूरों, दिहाड़ी और अस्थायी श्रमिकों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाने, पोस्टर-बैनर लगाने और लू से बचाव संबंधी संदेश प्रसारित करने पर जोर दिया गया है।

राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षण बोर्ड के प्रशिक्षण महानिदेशालय को लू से बचाव और प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया है, जिसमें लू के कारण, लक्षण, बचाव के उपाय, सुरक्षित कार्य पद्धतियां और प्राथमिक उपचार शामिल होंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और श्रम कल्याण महानिदेशालय के तहत अस्पतालों और औषधालयों को लू से संबंधित मामलों के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने तथा ओआरएस और अन्य आवश्यक सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य श्रम आयुक्त और खान सुरक्षा महानिदेशालय जैसी एजेंसियों को सुरक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी करने को कहा गया है। वहीं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और राष्ट्रीय कैरियर सेवा को अपने शिविरों के दौरान भी श्रमिकों के लिए ठंडे और हवादार कार्यस्थल तथा पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय ने सभी संबंधित संगठनों से इस संबंध में की गई कार्रवाई पर पाक्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है, ताकि समीक्षा और निगरानी की जा सके। मंत्रालय ने दोहराया कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए समय पर कदम उठाना और कड़ी निगरानी अत्यंत आवश्यक है।

माली में हुए आतंकी हमलों की भारत ने की कड़ी निंदा

नई दिल्ली। भारत ने माली में हुए आतंकवादी हमलों की निंदा की है और रक्षा मंत्री जनरल सादियो कामारा सहित पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि माली में कई जगहों को निशाना बनाकर किए गए आतंकवादी हमलों की भारत कड़ी निंदा करता है। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और इस मुश्किल समय में माली की सरकार और वहां के लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाते हैं। वक्तव्य में आतंकवादी हमले में माली के रक्षा और पूर्व सैनिक मामलों के मंत्री जनरल सादियो कामारा के निधन पर भी संवेदना व्यक्त की गई है। वहीं, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रयासों को भारत के समर्थन की बात कही गई है।

देश में एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की सौ फीसदी आपूर्ति बरकरार : सुजाता शर्मा

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि देश में घरेलू रसोई गैस एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की सप्लाई 100 फीसदी पर बनी हुई है, जबकि व्यावसायिक एलपीजी की सप्लाई 70 फीसदी तक बहाल कर दी गई है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज अंतर मंत्रालयी पत्रकार वार्ता में कहा कि ऊर्जा परिदृश्य को स्थिर करने एवं आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए कई प्रभावी उपाय लागू किए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और फार्मा, स्टील व कृषि क्षेत्रों को एलपीजी की प्लाई प्राथमिकता के आधार पर दी जा रही है। सुजाता शर्मा ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलो एफटीएल सिलेंडरों के ज़रिए होने वाली सप्लाई को भी लगभग दोगुना कर दिया गया है। मार्च से अब तक पूरे देश में 67 हजार से अधिक सिलेंडर ज़ब्त किए गए हैं, जबकि 1160 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं और 271 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि कल तक, 42,800 से अधिक पीएनजी उपभोक्ताओं ने MYPNGD.in वेबसाइट के माध्यम से अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि शिपमिन_इंडिया नाविकों के कल्याण और समुद्री संचालन में कोई रुकावट न आए, यह सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं, और पिछले 24 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज़ से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है। मुकेश मंगल ने कहा कि डीजी शिपिंग के कंट्रोल रूम को अब तक 7,920 कॉल और 16,800 ई-मेल मिली हैं। पिछले 24 घंटों में, 140 कॉल और 180 ई-मेल प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय ने अब तक भारतीय नाविकों की सुरक्षित वतन वापसी में सहायता की है, जिसमें पिछले 24 घंटों में लौटे 24 नाविक भी शामिल हैं। टेक्सटाइल्स मिनइंडिया के व्यापार सलाहकार बिपिन मेनन ने अपने संबोधन में कहा कि कपड़ा मंत्रालय एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, क्षेत्रीय क्लस्टर एसोसिएशन, डीजी शिपिंग और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ खास तौर पर बातचीत करके पश्चिम एशिया की स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है।

गंगा एक्सप्रेसवे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स

निवेशकों के लिए 'हाई-इंसेंटिव कॉरिडोर', सब्सिडी से सिंगल विंडो तक पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार

लखनऊ। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित हो रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स (आईएमएलसी) अब केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि हाई-इंसेंटिव इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में उभर रहे हैं। योगी सरकार द्वारा दी जा रही बहुस्तरीय सब्सिडी, टैक्स छूट, सिंगल विंडो सिस्टम और पीएलआई टॉप-अप जैसी सुविधाएं निवेशकों के लिए इसे देश के सबसे आकर्षक औद्योगिक गंतव्यों में बदल रही है।

सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित हो रहे इन आईएमएलसी को निवेश का बड़ा केंद्र बनाने के लिए बहुस्तरीय प्रोत्साहन नीति लागू की है, जिससे लागत कम और कारोबार आसान हो रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे आईएमएलसी में निवेश करने वाले उद्योगों को उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत एलिजिबल कैपिटल इनवेस्टमेंट (ईसीआई) पर 42 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही, 100% नेट एसजीएसटी रिइम्बर्समेंट (ईसीआई के 300 प्रतिशत तक) की सुविधा योग्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को दी जा रही है। इससे शुरुआती

निवेश लागत में भारी कमी आती है और उद्योगों की वित्तीय व्यवहार्यता मजबूत होती है।

राज्य सरकार ने विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। सरकारी भूमि पर फ्रंट-एंड लैंड सब्सिडी 80 प्रतिशत तक और कैपिटल सब्सिडी 35 प्रतिशत तक दी जा रही है। साथ ही, आईएमएलसी में स्थापित होने वाली इकाइयों को भूमि पंजीकरण पर 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी छूट का लाभ मिलता है, जिससे जमीन अधिग्रहण और स्थापना की प्रक्रिया बेहद किफायती हो जाती है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ऊर्जा और नवाचार पर विशेष ध्यान दिया गया है। एफडीआई और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों को 5 वर्षों तक 100 प्रतिशत बिजली शुल्क (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी) में छूट दी जा रही है। ग्रीन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 2.5 करोड़ रुपये तक का इंसेंटिव (50 प्रतिशत तक) उपलब्ध है। वहीं, रिसर्च एवं डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने हेतु 10 करोड़ रुपये तक का आरएंडडी ग्रांट भी दिया जा रहा है, जिससे अत्याधुनिक तकनीक और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा।

निवेश प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए 'निवेश मित्र' सिंगल विंडो पोर्टल को मजबूत किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर 500 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं, भूमि आवंटन, स्वीकृति और इंसेंटिव ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध है। इससे निवेशकों को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और समय की बचत होती है। गंगा एक्सप्रेसवे आईएमएलसी में स्थापित उद्योगों को केंद्र सरकार की पीएलआई योजना के साथ 30 प्रतिशत तक का अतिरिक्त टॉप-अप भी दिया जा रहा है। यह सुविधा विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रतिस्पर्धी बनाती है और बड़े निवेश को आकर्षित करने में मदद करती है।

प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे वाराणसी एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने किया स्वागत

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को दो दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच गए हैं। बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विशेष विमान एयर इंडिया वन से प्रधानमंत्री जैसे ही विमानतल पर उतरे।

वहां पहले से मौजूद प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्पगुच्छ देकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां स्वागत करने वालों में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक आदि भी रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री व विशिष्ट जनों से कुछ देर बातचीत की। इसके बाद एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री कड़ी सुरक्षा के बीच वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बरेका के लिए रवाना हो गए।

बरेका के अस्थाई हेलीपैड पर भी प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्मजोशी से आगे बढ़कर पुष्पगुच्छ देकर प्रधानमंत्री की अगवानी की। यहीं, प्रधानमंत्री का स्वागत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित प्रदेश के अन्य मंत्रियों ने किया।

सड़क हादसा, दूल्हे के भाई समेत चार की मौत

हमीरपुर। कानपुर-सागर नेशनल हाइवे पर सोमवार रात हुए हादसे में चार बारातियों की मौत हो गई। मृतकों में सहबाला (दूल्हे का भाई) भी है। हादसे की खबर मिलते ही दोनों गांवों में मातम पसर गया। दुल्हन की विदाई नहीं हो सकी। यह हादसा एक तेज रफ्तार ट्रक की ईको वैन में सीधी टक्कर से हुआ। इसी वैन में दूल्हे का भाई और अन्य बाराती सवार थे। हादसे में तीन बराती भी घायल हुए है। सूचना पाते ही डीएम अभिषेक गोयल व एसपी मृगांग शेखर पाठक मौके पर पहुंचे।

ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार, हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र के डामर गांव निवासी रमाकांत कुशवाहा की शादी महोबा जिले के कबरई थाना क्षेत्र के पहरा गांव निवासी संतराम कुशवाहा की पुत्री अंजू के साथ तय हुई थी। सोमवार रात बारात गांव से निकासी के बाद निजी वाहनों से कबरई जा रही थी। दूल्हे का भाई शशिकांत उर्फ आशीष (२२) अपने रिश्तेदारों के साथ गांव

के कमलेश यादव की ईको वैन से बारात जा रहा था। इको वैन मौदहा कोतवाली क्षेत्र के छिरका गांव के पास पेट्रोलपंप के सामने पहुंची तो कबरई से कानपुर जा रहे गिट्टी से लदे ट्रक ने टक्कर मार दी।

पुलिस ने बतय कि इससे वैन के परखच्चे उड़ गए। हादसे में दूल्हे के भाई शशिकांत, मोहन पुत्र रामसेवक, कमल यादव व रिठारी गांव निवासी जितेन्द्र की मौके पर मौत हो गई। वहीं उरदना गांव निवासी दिलीप कुमार पुत्र गणेश, तिन्दुही गांव निवासी रोहित पुत्र राधेश्याम व डामर गांव निवासी बाबू गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाते ही मौदहा कोतवाली प्रभारी संतोष सिंह मौके पर पहुंचे। इस दौरान डीएम और एसपी भी पहुंच गए। पुलिस ने वैन में फंसे घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे में भाई और नाते-रिश्तेदारों की मौत की सूचना मिलते ही दूल्हा रो पड़ा और दुल्हान के गांव में मातम पसर गया। शादी की रस्में सादगी के साथ संपन्न कराई गईं। दुल्हन की विदाई नहीं कराई गई। डीएम अभिषेक गोयल ने बताया कि हादसे में चार लोगों की मौत हुई है वहीं तीन अन्य बाराती घायल हुए है। हादसे के बाद ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है।

सड़क हादसे में चार युवकों की मौत और दो घायल

लखीमपुर खीरी। जिले में फरधान थाना क्षेत्र स्थित बेहजम रोड पर सोमवार देर रात तेज रफ्तार एक कार ने दो बाइकों में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों बाइकों पर सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर जांच शुरू कर दी।

क्षेत्राधिकारी नगर विवेक तिवारी ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों की पहचान हो गई हैं, जिनमें नीमगांव थाना क्षेत्र निवासी हितेश शुक्ला (42), सोनौरा गांव के हरि किशन (40), बासारा गांव के अनुज कुमार (35) और आदर्श शामिल हैं। वहीं, दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गये। घटना की जानकारी मिलते ही सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों तत्काल अस्पताल भिजवाया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है।

परिजनों से पूछताछ में पता चला है कि ये सभी छह लोग दो बाइक पर सवार होकर सोमवार रात एक शादी समारोह में गये थे। देर रात को लौटते समय तभी बेहजम रोड पर लखनापुर पुलिया के पास तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवारों को रौंदने के बाद कार अनियंत्रित सड़क किनारे बने गड्ढे में जा गिरी। अंधेरे का फायदा उठाकर कार सवार युवक भाग निकले।

क्षेत्राधिकारी ने बताया कि फरधान थाना पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर फरार कार सवारों की तलाश की जा रही है। तनाव को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने बाबा विश्वनाथ के दर पर टेका माथा

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम में भाग लेने यहां आए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज काशीपुराधिपति बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। मंदिर के गर्भगृह में विधिविधान से बाबा के पावन ज्योर्तिलिंग का अभिषेक कर अध्यक्ष नितिन नवीन ने विधिवत दर्शन-पूजन किया। इस मौके पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की ओर से मुख्यमंत्री ने बाबा के दरबार में पहली बार आए भाजपा अध्यक्ष नवीन को स्मृति चिंह और प्रसाद दिया।

इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी समेत उत्तर प्रदेश सरकार में उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, स्टाम्प राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविन्द्र जायसवाल, आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ दयाशंकर मिश्र 'दयालु', पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल भी मौजूद रहे। इससे पहले बाबतपुर एयरपोर्ट पर खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगवानी की।

एयरपोर्ट से भाजपा अध्यक्ष कड़ी सुरक्षा के बीच श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए रवाना हुए। बाबतपुर हवाई अड्डे से शिवपुर, अतुलानंद, पुलिस लाइन तिराहा, चौकाघाट, लहुराबीर, मैदागिन होते हुए वे विश्वनाथ मंदिर मंदिर पहुंचे।

इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता जगह-जगह पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत करते रहे। बाबतपुर हवाई अड्डे से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर कें यात्रा मार्ग पर बने स्वागत प्वाइंट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया।

ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, एक ही परिवार के दो युवकों की मौत

संत कबीरनगर। जिले में मंगलवार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे दोपहिया वाहन पर सवार एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह हादसा खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर बुधा कला गांव के पास हुआ जब मजदूरी के लिए मोटरसाइकिल पर सवार होकर जिला मुख्यालय खलीलाबाद जा रहे डारीडीहा गांव निवासी चंद्रभान, चन्द्रहास और चंदभूषण को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। थाना प्रभारी जयप्रकाश दुबे ने बताया कि तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने चंद्रभान (35) और चन्द्रहास (25) को मृत घोषित कर दिया, जबकि चंदभूषण का इलाज जारी है। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया। थाना प्रभारी ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपी चालक की तलाश की जा रही है।

आज की नारी केवल घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं : प्रभारी मंत्री

औरैया। जनपद में सदर ब्लॉक सभागार में नारी शक्ति जन आक्रोश अभियान के अंतर्गत एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार की मंत्री व जनपद की प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला मौजूद रहीं। प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि आज की नारी केवल घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि वह राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

उन्होंने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। सम्मेलन के दौरान महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी महिला सशक्तिकरण को समाज के समग्र विकास की आधारशिला बताया। कार्यक्रम के

समापन के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं ने ब्लॉक गेट पर पहुंचकर विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान जिलाध्यक्ष सर्वेश कठेरिया, सदर विधायक गुड़यि कठेरिया, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सौरभ भूषण शर्मा सहित अनेक महिलाएं और पदाधिकारी मौजूद रहे।

20 हजार में हो रही थी भ्रूण लिंग की जांच, स्वास्थ्य विभाग ने अल्ट्रासाउंड सेंटर सील कर जब्त की मशीन, संचालक भी हिरासत में

बागपत। जनपद में मंगलवार को बागपत मेरठ रोड स्थित एक अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर हरियाणा और बागपत स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की। टीम ने सेंटर को सील करते हुए उसके संचालक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मौके से अल्ट्रासाउंड मशीन भी जब्त कर ली गई। साथ ही करीब 20 हजार रुपये नकद बरामद हुए हैं।

कार्रवाई में शामिल डॉ मनप्रीत सिंह ने बताया कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग को इस सेंटर पर लंबे समय से अवैध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। इसी के आधार पर टीम ने अचानक बागपत पहुंच कर छापा मारा। सूचना मिलने पर बागपत स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। जांच के दौरान सामने आया कि सेंटर पर अवैध रूप से भ्रूण जांच का काम किया जा रहा था, जिसके लिए मोटी रकम वसूली जाती थी। टीम ने मौके से इस अवैध लेनदेन से जुड़े साक्ष्य भी जुटाए हैं। छापेमारी के बाद संचालक विपिन को हिरासत में लिया गया है। बागपत सीएचसी प्रभारी डॉक्टर विभाग राजपूत का कहना है कि हरियाणा की टीम द्वारा छापेमारी की गई थी। मौके से केंद्र संचालक अल्ट्रासाउंड करता पकड़ा गया है, और लिंग जांच के लिए दिए गए 20 हजार रुपये भी केंद्र संचालक के पास से बरामद हुए हैं जिनके सीरियल नंबर भी मिले गए हैं। इस प्रकरण में बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है।

इस घटना के बाद स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिला मुख्यालय के पास लंबे समय से चल रही इस गैरकानूनी गतिविधि की जानकारी स्थानीय स्तर पर न होना प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करता है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले की गहन जांच में जुटा है और इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।

आवारा कुत्तों के हमले में आठ वर्षीय बच्चे की मौत

सहारनपुर। जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र में आवारा कुत्तों के झुंड ने आठ वर्षीय एक बच्चे को मार डाला। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि लवीश (आठ)

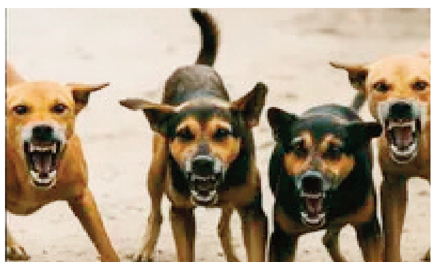

सोमवार शाम गांव के बाहर खेत से गेहूं की बालियां बीनने गया था और अकेला देखकर आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया।

थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह राणा ने बताया कि परिजनों की लिखित सूचना पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लवीश के चाचा सुमित ने बताया कि फोन पर बच्चे के लहूलुहान होने की सूचना मिली। परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लवीश चार भाई-बहनों में तीसरे नंबर पर था और गांव के स्कूल में कक्षा तीन का छात्र था। उसके पिता गांव में ही ट्रैक्टर-ट्रॉली में ईंट भरने का काम करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आवारा कुत्तों के हमलों से लोग पहले से परेशान हैं और ग्राम प्रधान और प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार शाम की इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत है और ग्रामीण बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

रानीपुर में फिर से लगेगा वस्त्र उद्योग, योगी सरकार ने क्लस्टर गठन को दी मंजूरी

झांसी। उत्तर प्रदेश सरकार झांसी के रानीपुर के कपड़ा उद्योग को पुनर्जीवित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक जिला एक उत्पाद की राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी ने रानीपुर में वस्त्र उद्योग के लिए क्लस्टर गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यहां क्लस्टर गठन के साथ ही कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया जाएगा और इसमें स्पेशल पर्पज व्हीकल तैयार होगा। इस काम पर 3.99 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

एक जिला एक उत्पाद में शामिल झांसी के वस्त्र उद्योग को विकसित करने को लेकर कुछ समय पहले प्रयास शुरू किए गए थे। इस प्रयास के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर एक डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट तैयार की गई थी। बुनकरों से बातचीत कर यह जानने की कोशिश हुई थी कि किन समस्याओं के कारण और किन सुविधाओं की कमी से इस काम में दिक्कतें आनी शुरू हुईं। यह रिपोर्ट एक

एक्सपर्ट संस्था ने विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से बातचीत और बेसलाइन सर्वे कर तैयार की थी। रानीपुर, मऊरानीपुर, उल्दन और आसपास के क्षेत्रों में किसी समय में बुनकरों की बड़ी संख्या हुआ करती थी, लेकिन सुविधाओं, संसाधनों और तकनीक के अभाव में धीरे धीरे ज्यादातर लोग इस काम को छोड़ते चले गए। अब झांसी के रानीपुर में क्लस्टर गठन को मंजूरी मिलने के बाद रानीपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट एक गांव में जमीन का चयन किया गया है। स्पेशल पर्पज व्हीकल के लिए 21 बुनकरों का एक समूह चयनित किया गया है। यह समूह एक कंपनी बनाएगी। यह कंपनी रजिस्टर्ड होगी। डीपीआर तैयार करने के बाद यहां भवन निर्माण शुरू होगा। इसके बाद यहां कैलेंडरिंग प्लांट, शटललेस लूम, डाइंग यूनिट, ड्राइंग यूनिट, शोकेस, रॉ मैटेरियल बैंक और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आसपास के क्षेत्रों के बुनकर निर्धारित दरों पर यहां उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। झांसी के उपायुक्त उद्योग

- योजना में 3.99 करोड़ खर्च कर अत्याधुनिक सुविधाओं की होगी स्थापना, स्थानीय बुनकरों को मिलेगी मदद
- एक जिला एक उत्पाद में शामिल वस्त्र उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए बुनकरों से मांगें गए थे सुझाव

मनीष चौधरी ने बताया कि झांसी के वस्त्र उद्योग को एक जिला एक उत्पाद में शामिल करने के बाद यहां के वस्त्र उद्योग को फिर से गति देने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसी कड़ी में रानीपुर में कामन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना को लेकर डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और अब रानीपुर में स्पेशल पर्पज व्हीकल के माध्यम से एक कंपनी का गठन कर यहां कॉमन फैसिलिटी सेंटर तैयार होगा। यहां वस्त्र उद्योग से जुड़ी अत्याधुनिक सुविधाएं बुनकरों को उपलब्ध कराई जाएंगी।

मायके में रह रही महिला ने दो बेटियों के साथ की आत्महत्या

कानपुर। जिला के महाराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने मायके में रह रही एक महिला ने मंगलवार को अपनी दो बेटियों के साथ कोई जहरीला पदार्थ खा कर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नजफगढ़ वासी परिवार की बेटी चांदनी की शादी मैनपुरी जिले के करहल नगला सीताराम निवासी राकेश से 12 साल पहले हुई थी।

दोनों की दो बेटियां पायल (8) और ब्यूटी (6) पैदा हुईं। चांदनी पिछले पांच साल से अपने मायके रहती थी। परिवार में उसकी मां शांति देवी भाई प्रताप, धर्मेंद्र, जितेंद्र भी रहते थे। मृतका के भाई धर्मेंद्र ने बताया कि शादी के बाद से ही चांदनी का पति शराब के नशे में उसे मरता पीटता था। रोज-रोज के लड़ाई झगड़े से परेशान होकर करीब पांच साल पहले वह मायके चली आयी थी। तीन साल पहले गांव की पंचायत में दोनों का तलाक भी हो चुका था। तब से वह मायके में ही रहकर

मजदूरी करती और अपनी दोनों बेटियों की परवरिश कर रही थी। उसने बताया कि आज काफी देर तक जब बहन और उसके बच्चे कमरे के बाहर नहीं दिखे तो अंदर जाकर देखा तो तीनों जमीन पर पड़े थे। आनन-फानन में उन्हें घाटमपुर सीएचसी लेकर जाया गया, लेकिन उन्हें हैलट रेफर कर दिया गया।

वहां पहुंचने पर चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस उपायुक्त पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि महिला के अपने बच्चों के साथ आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। परिजनों से पूछताछ की जा रही है। तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

SRH की चुनौती से पार पाकर जीत की राह पर लौटने की कोशिश करेगा मुंबई

मुंबई। पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को अगर अपनी किस्मत पलटनी है तो उसे शानदार फॉर्म में चल रहे सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बुधवार को यहां होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के महत्वपूर्ण मुकाबले में खेल के हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। मुंबई की टीम पहले सात मैचों में पांच में हार से चार अंक लेकर नौवें स्थान पर है। उसे चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 103 रन से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था जिससे उसका नेट रन रेट भी बिगड़ गया है।

मुंबई की टीम की चिंता भारत की टी20 विश्व कप विजेता टीम के चार खिलाड़ियों में शामिल कप्तान हार्दिक पंड्या (तीन विकेट और 97 रन) और सूर्यकुमार यादव (110) का खराब प्रदर्शन है। तिलक वर्मा के गुजरात टाइटन्स के खिलाफ आईपीएल में पहले शतक से मुंबई लगातार चार मैचों में हार का सिलसिला तोड़ने में सफल रहा था लेकिन चेन्नई से मिली करारी हार ने एक बार फिर उसके लड़खड़ाते अभियान को और भी मुश्किल में डाल दिया। मुंबई इंडियंस के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा है। वह अभी तक केवल दो विकेट ले पाए हैं। बुमराह बीच के ओवर और डेथ ओवरों में गेंदबाजी करते रहे हैं लेकिन पिछले दो मैच में उन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की क्योंकि अन्य गेंदबाज मुंबई को अच्छी शुरुआत दिलाने में नाकाम रहे थे। न तो ट्रेंट बोल्ट (एक विकेट) और ना ही दीपक चाहर (एक) अपने आक्रामक तेवर दिखा पाए हैं। मुंबई के गेंदबाजों के असफल होने के कारण विरोधी टीमों ने पावरप्ले में नियंत्रण बनाया है जिससे मुंबई को नुकसान पहुंचा। इस बीच रोहित शर्मा की अनुपस्थिति ने खालीपन सा पैदा कर दिया है। उनकी जगह पारी का आगाज करने के लिए भेजे गए दानिश मालेवार (2 और 0) उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए हैं।

अब यह देखना है कि पूर्व कप्तान रोहित हैमस्ट्रिंग की समस्या से उबरने के बाद पूरी फिटनेस हासिल कर पाए हैं या नहीं। चोटिल मिचेल सैंटनर की जगह केशव महाराज को टीम में शामिल किए जाने के बाद यह देखना बाकी है कि विल जैक्स को अंतिम एकादश में जगह मिलती है या नहीं। जैक्स ने टी20 विश्व कप में इसी तरह की परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन किया था। सनराइजर्स इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होगा कि मुंबई अपनी हार का सिलसिला तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ऐसे में उसकी उम्मीद बल्लेबाजों पर टिकी रहेगी जो वानखेड़े स्टेडियम की बल्लेबाजी के लिए अनुकूल परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। सनराइजर्स में पिछले मैच में वैभव सूर्यवंशी के शतक के बावजूद राजस्थान रॉयल्स को हराया था। अभिषेक शर्मा टी20 विश्व कप में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाने के बाद फॉर्म में लौट आए हैं और वह इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे।

उन्होंने अब तक 212.29 के स्ट्राइक रेट और 54.28 के औसत से 380 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं। ईशान किशन (312) और हेनरिक क्लासेन (349) ने भी बल्लेबाजी ने अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन ट्रैविस हेड (186) से टीम को और अधिक उम्मीदें होंगी, जो अभी तक इस टूर्नामेंट में खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। कप्तान पैट कमिंस की वापसी से सनराइजर्स का गेंदबाजी आक्रमण मजबूत हुआ है। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को उनसे सतर्क रहना होगा। सनराइजर्स की टीम अभी अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है।

इस प्रकार हैं टीम

- **मुंबई इंडियंस:** हार्दिक पंड्या (कप्तान), क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), रॉबिन मिंज (विकेटकीपर), दानिश मालेवार, शेरफेन रदरफोर्ड, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, विल जैक, मयंक रावत, नमन धीर, शार्दुल ठाकुर, अश्विनी कुमार, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, कृष भगत, एएम गजनफर, केशव महाराज, मयंक मारकंडे, मोहम्मद इज़हार, रघु शर्मा.
- **सनराइजर्स हैदराबाद:** पैट कमिंस (कप्तान), सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), ट्रैविस हेड, रविचंद्रन अश्विन, अनिकेत वर्मा, अभिषेक शर्मा, हर्ष दुबे, क्रेन्स फुलेट्रा, लियाम लिविंगस्टोन, कामिंडु मेंडिस, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, शिवम मावी, शिवांग कुमार, अमित कुमार, गेराल्ड कोएत्ज़ी, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन, दिलशान मदुशंका, ईशान मलिंगा, ओंकार तरनाले, जयदेव उनादकट, जीशान अंसारी।

मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा

चीन से 0-5 से हारकर भारत उबेर कप से बाहर, अब थॉमस कप पर निगाह

होर्सेंस (डेनमार्क)। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु मजबूत स्थिति में होने का फायदा नहीं उठा पाई जबकि अन्य खिलाड़ियों ने भी महत्वपूर्ण मौकों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जिससे भारत उबेर कप में चीन से 0-5 से हारकर इस बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गया। भारतीय महिला टीम ने मेजबान डेनमार्क से 2-3 की हार के साथ शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद उसने यूक्रेन पर 4-1 से जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीद बनाए रखी थी।

उबेर कप में 16 बार के चैंपियन चीन से भारत को पिछले तीनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। सिंधु ने भारत की तरफ से शुरुआत की जबकि उन्नति हुडा और तन्वी शर्मा की जगह अन्य दो एकल मुकाबलों के लिए ईशरानी बरुआ और देविका सिहाग को टीम में शामिल किया गया। सिंधु निर्णायक सेट में 18-12 से आगे थी लेकिन आखिर में वह विश्व की दूसरे नंबर की खिलाड़ी वांग झियी से 16-21, 21-19, 19-21 से हार गईं। इससे चीन ने सोमवार को ग्रुप ए के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।

सिंधु ने बाद में कहा, '''यह एक अच्छा मैच था। अगर मैं जीत हासिल करने में सफल रहती तो और भी अच्छा होता। मुझे मौके मिले, लेकिन ऐसा नहीं था कि कुछ अंक आसान थे। प्रत्येक अंक के लिए कड़ा मुकाबला हुआ। हम वास्तव में प्रत्येक अंक के लिए बहुत संघर्ष कर रहे थे।'' प्रिया कोंजेंगबम और श्रुति मिश्रा पहले युगल मुकाबले में विश्व की नंबर एक जोड़ी लियू शेंग शू और टैन निंग के सामने नहीं टिक पाईं और 11-21, 8-21 से हार गईं। इशारानी बरुआ ने तोक्यो ओलंपिक चैंपियन चेन युफेई के सामने कड़ी चुनौती पेश की लेकिन विश्व में 38वें नंबर की भारतीय खिलाड़ी ने पहले गेम में 20-19 पर एक आसान मौका गंवा दिया।

विश्व में चौथे नंबर की खिलाड़ी युफेई ने यह मैच 44 मिनट में 22-20, 21-13 से जीतकर चीन को 3-0 की अजेय बढ़त दिला दी। दूसरे युगल में त्रीसा जॉली और कविप्रिया सेल्वम की जोड़ी को 59 मिनट तक चले मुकाबले में लूओ जू मिन और झांग शू जियान से 10-21, 21-12, 19-21 से हार का सामना करना पड़ा। विश्व में 43वें नंबर की खिलाड़ी देविका सिहाग ने भी अच्छी शुरुआत की लेकिन वह लय बरकरार रखने में विफल रहीं और तीसरे एकल में विश्व में 97वें नंबर की खिलाड़ी जू वेन जिंग से 21-19, 17-21, 10-21 से हार गईं।

भारत की निगाहें अब पुरुष टीम पर टिकी हैं जो थॉमस कप में ग्रुप ए में अपने आखिरी मुकाबले में चीन का सामना करेगा। 2022 की चैंपियन भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया पर 5-0 की शानदार जीत से पहले ही क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत और चीन इस ग्रुप में शीर्ष पर हैं। भारत ने कनाडा पर 4-1 से जीत के साथ शुरुआत की थी। चीन ने अपने पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5-0 से हराया था। उसने सोमवार को कनाडा को 4-1 से पराजित किया। भारत और चीन अब बुधवार को अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में एक दूसरे का सामना करेंगे, जिससे ग्रुप में शीर्ष स्थान पर रहने वाली टीम का फैसला होगा।

मैराथन रिकॉर्ड धारक ने स्वयं कराए कई डोप टेस्ट

लंदन। दो घंटे से कम समय में मैराथन पूरी करने वाले पहले धावक सबास्टियन सावे ने यह रिकॉर्ड बनाने से पहले स्वयं ही डोपिंग के कई परीक्षण करवाए और उन्हें उम्मीद है कि वह दुनिया के सामने यह साबित कर देंगे कि वह पूरी तरह से साफ सुथरा होकर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कीनिया के इस धावक ने रविवार को लंदन मैराथन में एक घंटे, 59 मिनट और 30 सेकंड का समय लेकर वह कारनामा कर दिखाया जिसे लंबे समय से असंभव माना जा रहा था। कीनिया में हाल के वर्षों में कई प्रमुख धावक डोपिंग के दोषी पाए गए जिनमें महिला मैराथन में विश्व रिकॉर्ड धारक रूथ चेपनगेटिच भी शामिल हैं जिन पर तीन साल का प्रतिबंध लगाया गया था। इसलिए सावे ने अपने कोच और प्रबंधन टीम के साथ मिलकर अपने प्रदर्शन को लेकर किसी भी संदेह को दूर करने के लिए स्वेच्छा से 'कई' डोपिंग परीक्षण करवाए।

वायरस के खतरे के बीच एरीना सबालेंका क्वार्टर फाइनल में, कोको गॉफ और एलेना रायबाकिना बाहर

मैड्रिड। विश्व की नंबर एक खिलाड़ी एरीना सबालेंका ने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की बीमारी का कारण बने वायरस के खतरे और नाओमी ओसाका के जुझारू खेल से खुद को बचाते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इगा स्वियातेक, कोको गॉफ, मारिन सिलिच और कुछ अन्य खिलाड़ी पेट में संक्रमण से प्रभावित हुए हैं लेकिन सबालेंका ने कहा कि वह साधारण आहार करके बीमारी से बचने की कोशिश कर रही है।

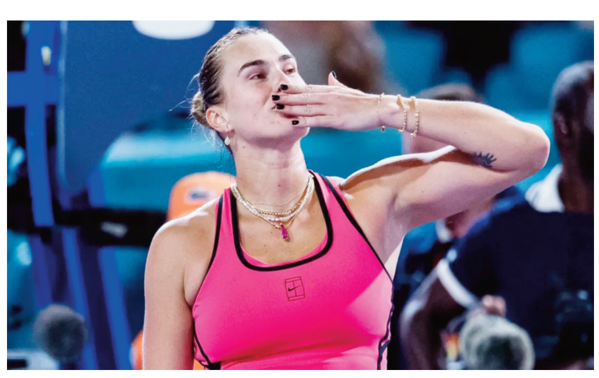

खिलाड़ियों के बीच यह अफवाह थी कि खराब झींगा टैको संक्रमण के लिए जिम्मेदार थे। सबालेंका ने कहा, ''अभी तक तो सब ठीक है। मैंने सुना है कि मुझे उन टैकोस से परहेज करना होगा। मैं वही खाना खा रही हूं, जो मैं टूर्नामेंट की शुरुआत से खा रही हूं।'' रविवार को सोराना सिर्स्टिया पर जीत के दौरान गॉफ ने कोर्ट पर उल्टी कर दी थी लेकिन सोमवार को लिंडा नोस्कोवा से 6-4, 1-6, 7-6 (5) से हार के दौरान अमेरिकी खिलाड़ी में बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखे। लिंडा नोस्कोवा पिछले साल उपविजेता रही थीं।

छह बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्वियातेक ने शनिवार को मैच के बीच से हटने के बाद कहा, ''मैंने सुना है कि कोई वायरस फैल रहा है। मेरी तबीयत बहुत खराब है।'' सिलिच शुक्रवार को जोआओ फोन्सेका के खिलाफ अपना मैच नहीं खेल सके। उन्होंने कहा, ''दुर्भाग्य से मुझे फूड पॉइज़निंग हो गई है। मैंने अपनी तरफ से काफी कोशिश की लेकिन मैं मैच खेलने की स्थिति में नहीं हूं।'' मौजूदा चैंपियन सबालेंका ने चौथे दौर के मुकाबले में ओसाका के खिलाफ एक सेट और एक ब्रेक से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की।

उन्होंने दो घंटे 20 मिनट तक चले मैच में 6-7 (1), 6-3, 6-2 से जीत हासिल की। सबालेंका का अगला मुकाबला अमेरिकी खिलाड़ी हेली बैपटिस्ट से होगा, जिन्होंने बेलिंडा बेनसिच को 6-1, 6-7 (14), 6-3 से हराया। विश्व की दूसरे नंबर की खिलाड़ी एलेना रायबाकिना भी अनास्तासिया पोटापोवा से सीधे सेटों में हार गईं।

पुरुष वर्ग में 19 वर्षीय राफेल जोडर ही एकमात्र स्पेनिश खिलाड़ी बचे हैं क्योंकि अन्य स्थानीय खिलाड़ियों में डेनियल मेरिडा स्टेफानोस सिटसिपास से 6-4, 6-2 से और एलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना मौजूदा चैंपियन कैस्पर रूड से 6-3, 6-1 से हार गए। विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी और स्पेन के मौजूदा शीर्ष खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज़ ने दाहिनी कलाई में चोट के कारण टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया था।

13 करोड़ के पार पहुंची एनएसई के रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की संख्या, 40% इन्वेस्टर 30 साल से कम उम्र के

नई दिल्ली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की संख्या के मामले में नया मुकाम हासिल कर लिया है। एनएसई के रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की संख्या 13 करोड़ के पार पहुंच गई है। एनएसई ने सोमवार यानी 27 अप्रैल के कारोबारी सत्र के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। इसके पहले सितंबर 2025 में एनएसई पर रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की संख्या 12 करोड़ के स्तर पर पहुंची थी। इस तरह सिर्फ सात महीने की अवधि में ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से एक करोड़ नए रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स जुड़ गए।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार एनएसई से जुड़े रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स में महिलाओं की संख्या में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। एनएसई के हर चार रजिस्टर्ड इन्वेस्टर में एक महिला है। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स की औसत आयु भी अब घट कर 33 साल हो गई है। इसके पहले साल 2021 में एनएसई के निवेशकों की औसत आयु 36 साल थी। स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड के मुताबिक इसके निवेशकों में लगभग 40 प्रतिशत संख्या 30 साल से कम उम्र के निवेशकों की है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स की संख्या में बढ़ोतरी की रफ्तार काफी तेज हो गई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स की संख्या एक करोड़ के स्तर तक पहुंचने में 14 साल की अवधि लगी थी। इसके बाद इन्वेस्टर्स की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी।

एक करोड़ इन्वेस्टर की संख्या पूरी करने के बाद अगले 11 साल में एनएसई के रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की संख्या चार करोड़ तक पहुंच गई। इसके बाद पिछले कुछ साल से स्टॉक एक्सचेंज से औसतन छह से आठ महीने की अवधि में ही एक करोड़ नए इन्वेस्टर जुड़ रहे हैं।

एनएसई के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की पांच साल की अवधि में रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की संख्या 26.4 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ी। इससे पहले के पांच साल की अवधि के दौरान ये दर 15.2 प्रतिशत थी। इसी अवधि के में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 18 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ कर 460.6 लाख करोड़ रुपये हो गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार देश के ज्यादातर हिस्सों के लोग रजिस्टर्ड इन्वेस्टर के रूप में एनएसई से जुड़ चुके हैं।

फिलहाल देश के 99.85 प्रतिशत पिन कोड (पोस्टल एरिया) में एनएसई के रजिस्टर्ड इन्वेस्टर मौजूद हैं। मतलब देश के हर जिले में तो में एनएसई के रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं ही, देश के ज्यादातर प्रखंडों तक एनएसई के रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स पहुंच गए हैं। अगर एनएसई के संख्यात्मक तौर पर राज्यवार सबसे अधिक इन्वेस्टर की बात करें, तो महाराष्ट्र लगभग दो करोड़ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स के साथ देश में सबसे अधिक इन्वेस्टर वाला राज्य है। रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर हैं, जहां रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की संख्या लगभग 1.5 करोड़ है। वहीं गुजरात लगभग 1.1 करोड़ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की संख्या के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

नीति आयोग ने भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यात्रा का रोडमैप किया लॉन्च

नई दिल्ली। नीति आयोग ने भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) यात्रा के अगले चरण के लिए एक रणनीतिक रोडमैप, "DPI@2047" लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए देश में समावेशी और तेज आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह पहल विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

आयोग के मुताबिक यह रोडमैप दो चरणों में काम करेगा, इसमें पहला डीपीआई 2.0 (2025–2035), जिसमें रोजगार और आजीविका बढ़ाने पर फोकस रहेगा, और दूसरा डीपीआई 3.0 (2035–2047) है, जिसमें व्यापक समृद्धि हासिल करने का लक्ष्य होगा। डीपीआई 2.0 के तहत एमएसएमई, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बदलाव लाने की योजना है। साथ ही, क्रेडिट, डिजिटल ट्रांजैक्शन, डेटा के बेहतर उपयोग और एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य डिजिटल सिस्टम को केवल पहचान, भुगतान और सरकारी योजनाओं तक सीमित न रखकर, उसे रोजगार, उत्पादकता और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना है।

कार्यक्रम के दौरान सुमन बेरी ने कहा कि अब विकास का फोकस सिर्फ जीडीपी पर नहीं, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने पर होना चाहिए। वहीं अजय कुमार सूद ने कहा कि तकनीक का सही उपयोग तभी संभव है जब उसे बड़े स्तर पर लागू किया जाए और उसमें भरोसा और सुरक्षा बनी रहे। वहीं, निधि छिब्बर ने बताया कि ये रोडमैप राज्यों को भी डिजिटल बदलाव में मदद करेगा, जिससे उनकी विकास गति तेज होगी। विशेषज्ञों के अनुसार डीपीआई और एआई के मेल से भारत एक ऐसा मॉडल बना सकता है, जो रोजगार बढ़ाने, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा।

कुल मिलाकर, यह रोडमैप भारत की डिजिटल यात्रा को एक नए चरण में ले जाने और व्यापक स्तर पर विकास सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

भारत-न्यूजीलैंड एफटीए के बाद 2030 तक 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर के निर्यात का लक्ष्य

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर करने के बाद देश के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली के भारत मंडपम में निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) और उद्योग जगत के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की। बैठक में बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य के संदर्भ में भारत के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने से जुड़ी रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में पीयूष गोयल ने कहा कि यह उपलब्धि विकसित भारत की परिकल्पना के अंतर्गत वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक आधार का काम करेगी। उन्होंने निर्यातकों और उद्योग जगत से आग्रह किया कि वे विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का पूरा लाभ उठाकर बाजार पहुंच बढ़ाएं, निर्यात को बढ़ावा दें और रोजगार के अवसरों का सृजन करें।

उन्होंने कहा कि इन समझौतों का समय पर उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।मंत्रालय के मुताबिक भारत मंडपम में भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर समारोह के दौरान आयोजित इस बैठक में 30 ईपीसी और शीर्ष उद्योग मंडलों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ वाणिज्य विभाग और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

डीजीएफटी ने निर्यात सुधार प्रारूप प्रस्तुत किया। उद्योग ने एमएसएमई की चुनौतियों को स्पष्ट किया। सरकार ने समर्थन और व्यापार सुगमता उपायों का आश्वासन दिया। इसके अलावा निर्यात प्रोत्साहन मिशन की प्रगति की समीक्षा की गई। पीयूष गोयल ने ईपीसी कंपनियों से निर्यातकों का आधार बढ़ाने और नए बाजारों की खोज करने का आग्रह किया।

स्नैबिट ने 'सीरीज-डी' वित्त पोषण दौर में 5.6 करोड़ डॉलर जुटाए

नई दिल्ली। घरेलू सेवाएं उपलब्ध कराने वाले मंच स्नैबिट ने 'सीरीज-डी' वित्त पोषण दौर में 5.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर (करीब 530 करोड़ रुपये) जुटाए हैं। कंपनी ने मंगलवार को बयान में बताया कि इस वित्त पोषण दौर का सह-नेतृत्व सस्क्वेहाना वेंचर कैपिटल, मिराए एसेट वेंचर इन्वेस्टमेंट्स के यूनिकॉर्न ग्रोथ फंड और बर्टेल्समैन इंडिया इन्वेस्टमेंट्स ने किया। मौजूदा निवेशकों नेक्सस वेंचर पार्टनर और लाइटस्पीड ने भी इस दौर में भाग लिया। स्नैबिट के संस्थापक एवं सीईओ आयुष अग्रवाल ने कहा कि कंपनी इस राशि का इस्तेमाल अपने बही-खाते को मजबूत करने, छोटे बाजारों में सेवाओं का विस्तार करने और निकट भविष्य में नई श्रेणियों में प्रवेश के लिए करेगी।'' उन्होंने कहा, ''हमने 'सीरीज-डी' वित्त पोषण दौर में 5.6 करोड़ डॉलर जुटाए हैं जिसका नेतृत्व एसआईजी ने किया है। साथ ही मिराए और बर्टेल्समैन भी इसमें शामिल हैं। '' इस नए निवेश के साथ कंपनी अब तक कुल 11.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटा चुकी है। 'सीरीज-डी' वित्त पोषण दौर स्टार्टअप या कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने का एक उन्नत एवं परिपक्व चरण है।

गूगल का 15 अरब डॉलर का डेटा सेंटर विशाखापत्तनम को एआई केंद्र बनाएगा: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव

तारलुवाड़ा (आंध्र प्रदेश)। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की बढ़ती डिजिटल क्षमता का उल्लेख करते हुए मंगलवार को कहा कि 15 अरब डॉलर के आगामी गूगल एआई डेटा सेंटर के साथ विशाखापत्तनम कृत्रिम मेधा (एआई) केंद्र के रूप में उभरेगा। विशाखापत्तनम के तारलुवाड़ा में 'गूगल क्लाउड इंडिया एआई डेटा सेंटर' के शिलान्यास समारोह में उन्होंने कहा कि यह पहल भारत के एआई आधारित डिजिटल ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती डिजिटल ताकत स्पष्ट है और 15 अरब डॉलर के गूगल एआई डेटा सेंटर के साथ विशाखापत्तनम एक प्रमुख एआई केंद्र बनने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विशाखापत्तनम एक 'एआई सिटी' में तब्दील होगा। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की दूरदर्शिता की सराहना की। उन्होंने कहा कि कृत्रिम मेधा शिक्षा, स्वास्थ्य, वैमानिकी, लॉजिस्टिक और कृषि जैसे क्षेत्रों में बदलाव ला रही है और इस एआई केंद्र के जरिये कई प्रमुख सेवाएं उपलब्ध होंगी।

रेल, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री वैष्णव ने कहा कि समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर के बाद परियोजना में तेजी से प्रगति हुई है और उन्हें विश्वास है कि जल्द ही प्रधानमंत्री द्वारा इस डेटा सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। भारत की प्रगति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश आईटी सेवाओं में अग्रणी बन चुका है और इलेक्ट्रॉनिक तथा सेमीकंडक्टर विनिर्माण में भी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत अब बड़ी संख्या में मोबाइल फोन का निर्यात कर रहा है और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक मांग का करीब 50 प्रतिशत पूरा कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन सहित इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और विनिर्माण में भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के प्रयास जारी हैं।

उन्होंने प्रौद्योगिकी कंपनियों से देश में सर्वर, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) तथा चिप के विनिर्माण का आग्रह किया। साथ ही इस संदेश को गूगल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुंदर पिचाई तक पहुंचाने का अनुरोध किया। वैष्णव ने विशाखापत्तनम से बिछाई जा रही समुद्री केबल के लिए गूगल का धन्यवाद किया, जिससे यूरोप, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के साथ वैश्विक संपर्क मजबूत होगी।

जब आपके साथ माता-पिता हों तो उनसे प्यार करें
अंकिता लोखंडे

मुंबई। हाल ही में अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने अपने दिवंगत पिता शशिकांत लोखंडे को याद करते हुए एक अत्यंत भावुक पोस्ट साझा की है। अंकिता के पिता शशिकांत लोखंडे का निधन लंबी बीमारी के बाद 2023 में हो गया था, जिससे अभिनेत्री और उनका परिवार गहरे सदमे में था। उन्होंने कहा है कि वह अपनी हर सांस में उन्हें याद करती हैं और माता-पिता के महत्व पर ज़ोर दिया है। अंकिता ने अक्सर अपने पिता के साथ अपने करीबी रिश्ते को सोशल मीडिया पर साझा किया है और उनके निधन के बाद भी उन्हें लगातार याद करती रहती हैं। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में, अंकिता ने अपने पिता के साथ की एक पुरानी और अनमोल तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर में अभिनेत्री अपने पिता के साथ एक खुशहाल पल साझा करती दिख रही हैं, जो उनके अटूट बंधन की गवाही देती है। तस्वीर के साथ अंकिता ने एक दिल को छू लेने वाला कैप्शन लिखा, मैं हर सांस में आपको याद करती हूं। यह छोटा सा वाक्य उनके पिता के प्रति उनके गहरे प्रेम और उनकी अनुपस्थिति के दर्द को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। अंकिता ने अपने प्रशंसकों और अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया, जिसमें उन्होंने माता-पिता के प्रति प्रेम और सम्मान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने आगे लिखा, जब आपके माता-पिता आपके साथ हों तो उनसे प्यार करें, वरना मेरा यकीन मानिए, बाद में आपको सिर्फ पछतावा होगा। यह शक्तिशाली संदेश उन सभी लोगों के लिए एक मार्मिक रिमाइंडर है जिनके माता-पिता अभी जीवित हैं, कि वे इस अमूल्य रिश्ते को संजोएं और बाद में किसी भी पछतावे से बचने के लिए अभी से उनके प्रति अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करें। यह अंकिता के अपने व्यक्तिगत अनुभव से उपजा ज्ञान है, जो कई लोगों को छू सकता है। वर्क फ्रंट पर, अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन इन दिनों एक नए और मनोरंजक रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स फन अनलिमिटेड के नए संस्करण में नज़र आ रहे हैं। इस शो में अर्जुन बिजलानी, करण कुंद्रा, एल्विश यादव, जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह, निया शर्मा, अभिषेक कुमार और समर्थ जुरेल जैसे कई अन्य लोकप्रिय टेलीविजन कलाकार भी शामिल हैं, जो दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं। अंकिता और विक्की अपनी केमिस्ट्री और मजेदार पलों से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। अंकिता ने अभिनय के क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक पवित्र रिश्ता में अर्चना मानव देशमुख के प्रतिष्ठित रोल से की थी, जिसने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत भी इस शो का हिस्सा थे, और उनकी जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था। यह शो तमिल टेलीविजन सीरीज थिरुमथी सेल्वम का रूपांतरण था। इसके बाद वह झलक दिखला जा 4 और कॉमेडी सर्कस जैसे रियलिटी शो में दिखीं। उन्होंने एक थी नायिका के दो एपिसोड में भी काम किया। 41 वर्षीय अभिनेत्री ने 2018 में कंगना रनौत स्टारर मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी से फिल्मों में डेब्यू किया। यह फिल्म रानी लक्ष्मीबाई की जिंदगी पर आधारित एक ऐतिहासिक ड्रामा थी, जिसमें अंकिता ने झलकारी बाई का दमदार किरदार निभाया था। अंकिता ने 2020 में साजिद नाडियाडवाला की एक्शन थ्रिलर फिल्म बागी 3 में भी काम किया था। यह बागी फ्रैंचाइज़ी का तीसरा पार्ट था, जिसमें टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख ने भी काम किया था। 2020 में, सुशांत सिंह राजपूत के गुजर जाने के बाद, उनका शो पवित्र रिश्ता दोबारा दिखाया गया।

लुक्खे के जरिए ओटीटी की दुनिया में कदम रखेंगी पलक तिवारी

मुंबई। जल्द ही अभिनेत्री पलक तिवारी बहुप्रतीक्षित म्यूजिकल एक्शन ड्रामा वेब सीरीज लुक्खे के जरिए ओटीटी की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए एक बड़ी खबर साझा की और बताया कि सीरीज का नया गाना जी लेंगे जल्द ही रिलीज होने वाला है, जिसने उनके प्रशंसकों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है। यह सीरीज चंडीगढ़ के जीवंत रैप कल्चर और अपराध की अंधेरी दुनिया के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें संगीत, एक्शन और ड्रामा का रोमांचक मिश्रण देखने को मिलेगा। अभिनेत्री ने गाने की एक छोटी सी झलक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के माध्यम से साझा की। इस वीडियो के साथ अभिनेत्री ने लिखा, प्यार और उम्मीद को थामे हुए, जी लेंगे के साथ। यह गाना रिलीज हो गया है। यह पोस्ट गाने के भावनात्मक पहलू और उसके मुख्य विषय को इंगित करती है, जो जीवन में मुश्किलों के बावजूद प्यार और आशा को बनाए रखने का संदेश देता है। टीजर को देखकर ऐसा लगता है कि यह गाना सीरीज के भावनात्मक कोर का प्रतिनिधित्व करेगा, जहाँ संघर्ष के बीच भी मानवीय रिश्तों की गर्माहट और उम्मीद की किरण मौजूद रहती है। इस गाने की खास बात यह है कि इसमें मशहूर रैपर और गायक किंग के साथ भार्ग और रुआके जैसे प्रतिभाशाली कलाकारों ने अपनी आवाज दी है। किंग, जो अपनी अनूठी स्टाइल और दमदार गीतों के लिए जाने जाते हैं, उनकी उपस्थिति इस गाने को और भी खास बनाती है। गाने के टीजर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह एक इमोशनल ट्रैक होगा, जो प्यार और उम्मीद की कहानी बयां करेगा, जिससे दर्शक आसानी से जुड़ पाएंगे। संगीत प्रेमियों और सीरीज के प्रशंसकों के लिए यह गाना एक महत्वपूर्ण रिलीज साबित हो सकता है। पलक तिवारी की यह डेब्यू सीरीज अमेजन प्राइम पर 8 मई से स्ट्रीम हो रही है, जिससे उनके प्रशंसकों को उन्हें एक नए अवतार में देखने का मौका मिलेगा। हालांकि, सीरीज में पलक के किरदार को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, जिससे दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई है कि वह किस तरह की भूमिका निभाएंगी और कहानी में उनका क्या योगदान होगा। उनके किरदार की रहस्यमय प्रकृति सीरीज के प्रति जिज्ञासा को बनाए रखती है। सीरीज की कहानी चंडीगढ़ के रैप कल्चर और स्ट्रीट राइवेलरी पर आधारित है, जो युवा महत्वाकांक्षाओं और आपराधिक अंडरवर्ल्ड के बीच की टक्कर को दर्शाती है। यह बदले और महत्वाकांक्षा की एक गहरी दास्तान है, जिसमें एमसी बदनाम (किंग) और ओजी (शिवांकित) आमने-सामने हैं। उनके बीच का संघर्ष ही कहानी को आगे बढ़ाता है और इसमें कई ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे। हिमांक गौड़ द्वारा निर्देशित सीरीज लुक्खे का निर्माण ओपटीमिस्टिक्स एंटरटेनमेंट और व्हाइट गुरिल्ला एलएलपी के बैनर तले विपुल डी. शाह और राजेश बहल ने किया है। कहानी और स्क्रिप्ट अग्रिम जोशी और देबोजीत दास पुरकायस्थ ने लिखी और प्रोड्यूस की है, जिससे इसकी रचनात्मकता और गुणवत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है। आठ-एपिसोड की इस सीरीज में राशि खन्ना और किंग मुख्य भूमिका में नज़र आएंगे। साथ ही पलक तिवारी और लक्षवीर सिंह सरन भी अहम रोल में हैं, जो कहानी को मजबूती प्रदान करेंगे।

नागार्जुन की 100वीं फिल्म की शूटिंग शुरू

साउथ भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन अपनी 100वीं फिल्म को लेकर लंबे समय से चर्चा में हैं। फिलहाल 'किंग 100' के अस्थायी शीर्षक से बन रही इस फिल्म को निर्देशन रा कार्तिक कर रहे हैं। निर्माताओं ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है कि फिल्म अब प्री-प्रोडक्शन चरण से आगे बढ़कर मुख्य शूटिंग के चरण में पहुंच चुकी है और इसकी शूटिंग कई शेड्यूल में पूरी की जाएगी। फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें अभिनेत्री तब्बू भी अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी। नागार्जुन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि तब्बू को जब उनकी 100वीं फिल्म के बारे में पता चला तो उन्होंने खुद इस खास परियोजना का हिस्सा बनने की इच्छा जताई थी। दोनों कलाकारों को आखिरी बार 1998 की तेलुगु फिल्म 'आविदा मां आविडे' में साथ देखा गया था। 'किंग 100' का निर्माण नागार्जुन के अपने बैनर अन्नपूर्णा स्टूडियो के तहत किया जा रहा है। हालांकि फिल्म की कहानी को फिलहाल पूरी तरह गोपनीय रखा गया है, लेकिन निर्माताओं का कहना है कि यह एक भावनात्मक गहराई वाली मुख्यधारा की फिल्म होगी, जिसमें मनोरंजन और संवेदनशील कहानी का संतुलन देखने को मिलेगा। फिल्म को तेलुगु के साथ हिंदी, तमिल और अन्य भाषाओं में भी रिलीज करने की योजना बनाई जा रही है। नागार्जुन हाल ही में रजनीकांत की फिल्म 'कुली' में नजर आए थे, जबकि तब्बू हाल में 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में रही हैं। ऐसे में दोनों सितारों की यह वापसी दर्शकों के लिए खास मानी जा रही है।

इंडोनेशिया में दर्दनाक हादसा आपस में टकराई दो ट्रेन, कई लोगों की मौत

जकार्ता। इंडोनेशिया में जकार्ता के पास दो ट्रेनों की भीषण टक्कर में 14 लोगों की मौत हो गई और 81 घायल हैं। टैक्सी की टक्कर के बाद ट्रैक पर रुकी ट्रेन से हादसा हुआ। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के पास हुए एक बड़े रेल हादसे ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। रात के समय दो ट्रेनों की जोरदार टक्कर में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई, जबकि 81 लोग घायल हो गए।

हादसे के तुरंत बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा और मलबे में फंसे यात्रियों को निकालने का काम शुरू किया। प्रशासन, सेना और राहत एजेंसियां मिलकर तेजी से राहत कार्य में जुटी हुई हैं। सरकारी रेलवे कंपनी केरेटा एपी इंडोनेशिया (केएआई) की प्रवक्ता अन्ना पुरबा ने स्थानीय मीडिया को बताया कि ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या सात है, जबकि 81 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बचावकर्मी अब भी मलबे में फंसे दो जीवित लोगों तक पहुंचने की कोशिश

कर रहे हैं। कैसे हुआ हादसा? हादसे में बची एक यात्री ने बताया कि टक्कर बेहद भयावह थी। 29 वर्षीय सौसान सारिफाह ने अस्पताल से बताया कि वह काम से घर लौट रही थी, तभी बेकासी तैमूर स्टेशन के पास उनकी ट्रेन रुकी हुई थी। अचानक दूसरी लंबी दूरी की ट्रेन आकर उससे टकरा गई। उन्होंने कहा कि सब कुछ कुछ ही सेकंड में हुआ, मुझे लगा मैं बच नहीं पाऊंगी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि यात्री एक-दूसरे पर गिर पड़े और कई लोग डिब्बों में फंस गए। वहीं, रेलवे प्रवक्ता फ्रानोटो विबोवो ने बताया कि, एक टैक्सी ने रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन को हल्की टक्कर मार दी, जिससे वह ट्रैक पर रुक गई और पीछे से आ रही दूसरी ट्रेन उससे टकरा गई।

हादसे के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई, एंबुलेंस की लंबी कतार लग गई और घायलों को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। राहत-बचाव की कई टीमें मौके पर मौजूद है और घायलों को सुरक्षित ट्रेन से बाहर निकालने का काम कर रही हैं। इंडोनेशिया में पहले भी हुए हैं ट्रेंन हादसे गौरतलब है कि इंडोनेशिया में इस तरह के हादसे पहले भी हो चुके हैं। जनवरी 2024 में पश्चिमी जावा में एक ट्रेन दुर्घटना में चार कर्मचारियों की मौत हुई थी। वहीं 2015 में जकार्ता में कम्यूटर ट्रेन और मिनीबस की टक्कर में 16 लोगों की जान गई थी। विशेषज्ञों के मुताबिक, पुराने वाहनों और रखरखाव की कमी ऐसे हादसों की बड़ी वजह हैं।

ईरान परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन का उपाध्यक्ष बना, अमेरिका भड़का

न्यूयॉर्क। अमेरिका ने ईरान को संयुक्त राष्ट्र चार्टर विशेष समिति और परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन का उपाध्यक्ष चुने जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले ईरान को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का भी उपाध्यक्ष चुना जा चुका है। अमेरिका के तेवर संयुक्त राष्ट्र में सोमवार को परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बनी संधि की समीक्षा शुरू होने पर दिखे। बैठक में अमेरिका और ईरान के बीच तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तीखी बहस हुई।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में हथियार नियंत्रण और अप्रसार मामलों के लिए अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने कहा कि भले ही ईरान के इरादों और उसके परमाणु कार्यक्रम से निपटने के तरीकों को लेकर अलग-अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन ईरान ने संधि की अवमानना की है। येव ने कहा, ₹इस समीक्षा सम्मेलन का इस्तेमाल परमाणु अप्रसार संधि की अखंडता की रक्षा करना है। सम्मेलन में ईरान को जवाबदेह भी ठहराया जाना चाहिए। येव ने कहा कि हमने ईरान को ही

उपाध्यक्ष चुन लिया है। अमेरिकी नेता ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है और इस सम्मेलन की विश्वसनीयता पर एक धब्बा है।

वियना स्थित संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत रजा नजाफी ने अमेरिका के आरोपों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने समीक्षा सम्मेलन के उपाध्यक्ष के तौर पर अमेरिका की उम्मीदवारी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने अमेरिका पर संधि का सीधा उल्लंघन करने, परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने और इजराइल का समर्थन करके मध्य-पूर्व को परमाणु हथियारों से मुक्त बनाने की दिशा में हो रही प्रगति में बाधा डालने का आरोप लगाया। इस सम्मेलन में कुल 34 उपाध्यक्ष होते हैं। परमाणु अप्रसार संधि में शामिल 191 सदस्य देश इसकी हर पांच साल में समीक्षा करते हैं। यह संधि 1970 में लागू हुई थी। उपाध्यक्ष के तौर पर ईरान की दावेदारी का गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने समर्थन किया। इसमें 121 विकासशील देश शामिल हैं। उपाध्यक्ष पद पर अमेरिका की दावेदारी का ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात ने समर्थन किया है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की। रूस ने ईरान को निशाना बनाए जाने पर आपत्ति जताई है।

ईरान: विदेशमंत्री अराघची 48 घंटे में तीसरी बार पहुंचे पाकिस्तान, रूस भी मध्यस्थता को तैयार

तेहरान/मास्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 27 अप्रैल को मुलाकात करने के बाद ईरान के विदेशमंत्री अब्बास अराघची एक बार फिर पाकिस्तान पहुंचे हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ होर्मुज जलडमरूमध्य पर चल रहे टकराव के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। पुतिन ने कहा कि रूस मध्य पूर्व में जल्द से जल्द शांति सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने को तैयार है।

ईरान के प्रेस टीवी और रूस की समाचार एजेंसी तास की रिपोर्ट के अनुसार, अराघची के पाकिस्तान पहुंचने के बाद अमेरिका-ईरान युद्ध खत्म होने को लेकर अटकलें तेज हो गई है। दोनों देशों के बीच पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। वह ईरान-अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत को आगे बढ़ाने में सक्रिय है।

अराघची मंगलवार को रूस दौरे के बाद एक बार फिर 48 घंटे में तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे हैं।

इससे पहले अराघची रविवार रात पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख मुनीर से मिलने के बाद इस्लामाबाद से सीधे रूस रवाना हुए थे। उन्होंने कल सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब डेढ़ घंटे बैठक हुई। ईरान के विदेशमंत्री ने कहा कि बैठक में युद्ध और आक्रामकता से जुड़े मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श हुआ। उन्होंने ईरान-रूस संबंधों को रणनीतिक साझेदारी बताया और संकट के दौरान रूस के समर्थन के लिए आभार जताया। पुतिन ने भी पश्चिम एशिया में शांति बहाली के प्रयासों का समर्थन करने की बात कही और उम्मीद जताई कि जल्द ही क्षेत्र में स्थिरता लौटेगी।

FBI ने एलन को कोर्ट में पेश किया, चुपचाप खड़ा रहा, हलफनामे में ट्रंप की हत्या के प्रयास का आरोप

वाशिंगटन। अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने शनिवार को वाशिंगटन हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस पत्रकारों के डिनर में गोलीबारी करने वाले आरोपित कोल एलन को संघीय अदालत में पेश किया। उसने अपने पक्ष में कोई दलील नहीं दी और चुपचाप खड़ा रहा।

एफबीआई ने अदालत में एक हलफनामा दाखिल किया। इसमें एलन पर सबसे बड़ा आरोप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश करने का लगाया गया है। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार एलन को सोमवार दोपहर पहली बार संघीय अदालत में पेश किया गया। वाशिंगटन डीसी के अमेरिकी अटॉर्नी जीनिन पिरो ने कहा कि संदिग्ध पर तीन आरोप लगाए गए हैं। मगर और भी आरोप जोड़े जा सकते हैं। एफबीआई के एक

हलफनामे में कहा गया है कि एलन पिछले हफ्ते लॉस एंजिल्स से ट्रेन से वाशिंगटन आया। व्हाइट हाउस पत्रकारों के डिनर से एक दिन पहले वाशिंगटन हिल्टन में रुका। सरकारी वकीलों ने अदालत को बताया कि एलन होटल के बॉलरूम के ऊपर वाली मंजिल पर बने सुरक्षा जांच केंद्र में जबरदस्ती घुसा। उसके पास एक शॉटगन और एक हैंडगन थी।

हलफनामे में यह स्पष्ट नहीं है कि उसकी चलाई गोली ही सीक्रेट सर्विस एजेंट की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी। उल्लेखनीय है कि सीक्रेट सर्विस को इस कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर सवालों का सामना करना पड़ रहा है। इस कार्यक्रम में 2,500 पत्रकार, सरकारी अधिकारी, सांसद और मशहूर हस्तियां मौजूद थीं। कई लोगों ने कहा कि उन्हें सुरक्षा व्यवस्था ढीली लगी। सीक्रेट सर्विस ने सोमवार को कहा कि वह भविष्य के कार्यक्रमों में सुरक्षा बढ़ाएगी। इस घटना के बाद सीनेट के रिपब्लिकन सांसदों के एक समूह ने सोमवार को एक बिल का प्रस्ताव रखा।

इस बिल के तहत व्हाइट हाउस से जुड़ा एक बॉलरूम बनाने के लिए सरकारी पैसों का इस्तेमाल करने की अनुमति मिल जाएगी। इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन हासिल है। ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल निजी पैसों से एक बॉलरूम बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ट्रंप और कांग्रेस के रिपब्लिकन सदस्यों ने तर्क दिया है कि शनिवार की गोलीबारी से सबक लेते हुए व्हाइट हाउस परिसर में एक बड़ा इवेंट स्पेस सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है।

इसका समर्थन पेंसिल्वेनिया के डेमोक्रेटिक सीनेटर जॉन फेटरमैन ने भी किया है। साउथ कैरोलिना के रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह एक ऐसा बिल पेश करने की योजना बना रहे हैं, जो भूमिगत बॉलरूम बनाने के लिए 400 मिलियन डालर की मंजूरी देगा। इस बॉलरूम में सीक्रेट सर्विस और अन्य सुरक्षा सुविधाएं भी होंगी। इस प्रोजेक्ट का खर्च कस्टम फीस से पूरा किया जाएगा।